असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

15 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा **मंगलवार,तिथि 15 मार्च,2016**

द्वितीय सत्र **25फाल्गुन,1937(शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया**)**

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर-काल । तारांकित प्रश्न सं0-518 ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, पूरे राज्य में पानी का संकट खड़ा हो गया है, पूरे राज्य में पेयजल का संकट खड़ा हो गया है, आम जनता को पानी नहीं मिल रहा है । पानी का लेयर भाग गया है और हजारों चापाकल राज्य में बन्द पड़े हुए हैं ।

महोदय, पूरे राज्य में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है, गर्मी पड़ने के कारण लगातार पानी का लेयर नीचे भाग गया है । हजारों चापाकल बन्द हैं, ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना ठप्प है । शहरों में भी पानी नहीं मिल रहा है । चापाकल की जो योजना थी, उसको सरकार ने बन्द करने का निर्णय लिया है, इससे लोगों में काफी आक्रोश है । हम चाहते हैं कि इसपर सरकार का वक्तव्य हो ।

अध्यक्ष : माननीय प्रेम बाबू, आप जो कह रहे हैं, वह मुद्दा महत्वपूर्ण है लेकिन क्या उसको उठाने का यही समय है ?

श्री प्रेम कुमार : बिल्कुल । इसलिए महोदय, क्वेश्चन आवर से बड़ा मुद्दा पानी का है । पूरे बिहार में पीने का पानी जनता को नहीं मिल रहा है .....

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न सं0-518(श्री श्याम रजक)

श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा : महोदय, यह स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित हो गया था, लेकिन वहां से रिपोर्ट आज ही प्राप्त हुआ है और जवाब अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका जवाब बाद में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अध्यक्ष : ठीक है, यह स्थगित होगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

श्री प्रेम कुमार : पूरे राज्य में पानी का संकट है । पानी में आर्सेनिक पाया जा रहा है और सरकार चापाकल योजना को बन्द करने का काम कर रही है .....

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-1275(श्री यदुवंश कुमार यादव)

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिला के वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत विभाग द्वारा स्टेडियम निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं है।

2. अस्वीकारात्मक है ।

3. विभागीय पत्रांक-255 दिनांक 14.03.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल से विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गयी है । जिला पदाधिकारी, सुपौल से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्विवाद सरकारी भूमि एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर स्टेडियम निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : माननीय मंत्री जी, कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगा गया है, वहां से रिपोर्ट आने के बाद हम उसको करायेंगे ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-1276(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय, 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वर्ष 2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का परिसीमन वार्ड के परिसीमन के अनुरूप करने का मात्र निर्णय लिया गया था ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

जिला पदाधिकारी,औरंगाबाद के पत्रांक-623 दिनांक 29.02.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि औरंगाबाद जिला में 2136 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है, जिनके विरूद्ध 2015 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत है तथा शेष 121 केन्द्रों पर सेविका/सहायिका के चयन की कार्रवाई की जा रही है ।

3. उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

निदेशालय के पत्रांक 3401 दिनांक 17.06.2014 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से 41,188 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके विरूद्ध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 14-1/2013-सी0डी0-1, दिनांक 01. 12. 2014 द्वारा 23,041 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है । नव

स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना व्यय हेतु आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के पत्रांक-551 दिनांक 29.02.2016 द्वारा भारत सरकार से राशि की मांग की गई है । राशि प्राप्त होने के पश्चात् नव स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रियाशील करने की कार्रवाई की जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मुझे सुनाई नहीं पड़ा तो मैं पूरक क्या करूँ !

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उनको उत्तर की कॉपी भेजवा दीजियेगा ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : भेजवा दूँगी ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-1277(श्री नौशाद आलम)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. विभागीय संकल्प 1021 दिनांक 05.07.2013 में निहित प्रावधान के तहत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नगत पंचायत में निर्दिष्ट मापदण्डयुक्त विद्यालय के उत्क्रमण पर विचार किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1278(श्री अजीत शर्मा)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

एस0एस0 बालिका उच्च विद्यालय,नाथनगर में 1254 एवं वर्ग दशम् में 895 छात्रायें नामांकित हैं । उक्त विद्यालय को कुल 15 वर्ग कक्षा उपलब्ध है, जिसमें पठन-पाठन का कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।

(2) एवं (3) - छात्राओं की अधिकतम उपस्थिति के कारण वर्ग संचालन हेतु बरामदे का उपयोग किया जाता है ।

राज्य संसाधन उपलब्धता के उपरांत विद्यालय में अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री अजीत शर्मा : समय-सीमा तय किया जाय, सर ।

श्री अशोक चौधरी : अगले वित्तीय वर्ष में ।

तारांकित प्रश्न सं0-1279(श्री विद्या सागर केशरी)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-1280 (श्री सरोज यादव)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

जिला पदाधिकारी,भोजपुर, आरा के पत्रांक-362, दिनांक 11.03.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला स्तरीय एवं परियोजना स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की करायी जा रही जॉच एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,आरा ग्रामीण, आरा सदर, बड़हरा एवं कोईलवर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भोजपुर जिला अन्तर्गत बड़हरा, कोईलवर एवं आरा प्रखण्डों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित संचालन किया जा रहा है ।

श्री सरोज यादव : महोदय, हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे केन्द्र हैं, जो बन्द रहते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है और वहां पर जो बच्चे छोटे-छोटे हैं, उनको कभी भी पोषाहार नहीं बांटा जाता है । हमारे क्षेत्र में बड़हरा, कोईलवर एवं आरा प्रखंड है । मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चे नहीं जाते हैं और आंगनबाड़ी केन्द्र कभी चलाया नहीं जाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा करें । श्रीमान् एक जगह की समस्या नहीं है, सब जगह की यह समस्या है ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1281(श्री रत्नेश सादा)</u>

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखण्ड के किसनपुर के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्रस्ताव की मांग की गयी है ।

3. जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि मिलने पर निधि की उपलब्धता के आधार पर स्टेडियम के निर्माण किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से समय सीमा तय करने का आग्रह करता हूँ ।

अध्यक्ष : समय-सीमा ?

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, कह रहे हैं कि अगला वित्तीय वर्ष जो आ रहा है, उसमें पास करवा देंगे ।

श्री रत्नेश सादा : बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी ।

टर्न:2/अंजनी/दि0 15.3.16

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-1282(श्री विजय कुमार खेमका)

(व्यवधान)

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण योजना के तहत पूर्णियां पूर्व प्रखंड में वर्ष 2008-09 में स्टेडियम निर्माण की योजना स्वीकृत है तथा इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

2. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । अत: बाकी के स्थानों पर स्टेडियम निर्माण संभव नहीं है ।

3. उत्तर-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1283(श्री मिथिलेश तिवारी)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-1284(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-1285(श्री राजीव नंदन)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-1286(श्री केदार नाथ सिंह)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-1287(श्री संजय सरावगी)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-1288(श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा कराये गये गृह आधारित सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में 06-14 आयु वर्ग के नि:शक्त बच्चों की संख्या 2.4 लाख लगभग है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि 2.4 लाख बच्चों के विरूद्ध 1.9 लाख बच्चे राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं ।

3. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार शिक्षा परियोजना, समस्तीपुर में 06-14 आयु वर्ग के लगभग 10,000 नि:शक्त बच्चे प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित हैं ।

4. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् अंतर्गत नि:शक्त बच्चों के लिए विशेष विद्यालय संचालित करने का प्रावधान नहीं है । राज्य के सभी प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों में 06-14 आयु वर्ग के नि:शक्त बच्चों के पठन-पाठन हेतु व्यवस्था है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, विकलांग बच्चों से जुड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी के दर्द को नहीं समझते हैं । महोदय, जवाब मुझे उपलब्ध करा दिया जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-1289(श्री सत्यदेव सिंह)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

पार्क के अन्दर गंदगी नहीं है । पार्क के बाहर सफाई एवं रख-रखाव का जिम्मा वन विभाग के अधीन नहीं है ।

2- नवम्बर, 2015 में यह पार्क पर्यावरण एवं वन विभाग को दिया गया । राशि नगर विकास विभाग से प्राप्त नहीं हो सकी है । सामान्य रख-रखाव विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

3- पार्क के निर्माण कार्य में अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1290(श्री फैयाज अहमद)

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत मधुबनी जिला के विस्फी प्रखंड के उच्च विद्यालय, नाहस खंगरैठा में स्टेडियम निर्माण हेतु अब तक कुल 28.00 लाख की राशि विमुक्त की जा चुकी है। उक्त स्टेडियम निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रगति की मांग जिला पदाधिकारी, मधुबनी से की गयी है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

3- जिला पदाधिकारी, मधुबनी से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1291(डॉ0 मो0 जावेद)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-1292(श्रीमती प्रेमा चौधरी)

श्री अब्दुल जलील मस्तान : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- अंशतः स्वीकारात्मक है ।

3- अस्वीकारात्म्क है ।

वित्त विभाग के सहमति के उपरान्त नया निबंधन कार्यालय खोले जाने का मापदंड निर्धारित है । पातेपुर प्रखंड में नया निबंधन कार्यालय खोले जाने के संदर्भ में समाहर्त्ता-सह-जिला निबंधक, वैशाली का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जिसके आलोक में पातेपुर प्रखंड के क्षेत्र का विगत् तीन वर्षों में निर्धारित औसतन न्यूनतम 8000 दस्तावेज का निबंधन के स्थान पर मात्र 3477 दस्तावेज प्रतिवेदित है ।

अतः पातेपुर में निबंधन कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1293(श्री मो0 नेमतुल्लाह)

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, 1- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुतः विभागीय अधिसूचना 2214/एम0 दिनांक 27.08.13 के द्वारा निरूपित नई बालू नीति,2013 के परिशिष्ट-1 कंडिका-7 की उप कंडिका-xi के आलोक में बालू लदे सभी वाहनों को तारपोलिन से ढ़क कर बालू का परिवहन करना अनिवार्य किया गया है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

उपर्युक्त कंडिका-1 में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त विभागीय पत्रांक 1825/एम0 दिनांक 28.05.15 तथा 3140/एम0 दिनांक 14.08.15 द्वारा भी बालू लदे सभी वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिचालन हेतु निदेश दिया गया है ।

3- उपर्युक्त कंडिका-1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, बालू लदे ट्रैक्टर में कवर नहीं रहने के वजह से आये दिन दुर्घटना होती रहती है । आंख में लाल बालू लगता है और पीछे से आ रहे मोटरसाईकिल, साईकिल किसी वाहन से टकरा जाते हैं, जिसके कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है, अतः सरकार इसकी कोई-न-कोई सुनिश्चित व्यवस्था करे ताकि दुर्घटना होने से रोका जा सके ?

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, सरकार ने जो जानकारी दी, इसके बावजूद भी माननीय सदस्य ने जिस बात की सूचना दी है, उस सूचना को सरकार ग्रहण करती है और सरकार इसपर कार्रवाई करेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1294(श्री बशिष्ठ सिंह)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-1295(श्री रामविलास पासवान)

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है । अतः भागलपुर जिला के पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र के पीरपैंती एवं कहलगांव प्रखंड में एक-एक स्थान पर ही स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है ।

2- जिला पदाधिकारी,भागलपुर से उक्त प्रसंग में प्रस्ताव की मांग की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस वित्तीय वर्ष में बनेगा ?

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, इस वित्तीय वर्ष .....

श्री रामविलास पासवान : समय आप कब दे रहे हैं, कबतक बनेगा ?

अध्यक्ष : कबतक बनेगा ?

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है, वहां के जिला पदाधिकारी को हमने लिखा है, वहां से आ जायेगा तो इसके बाद हम राशि दे देंगे, वे वहां से इसको करा लेंगे । जब जिला पदाधिकारी से प्रस्ताव आ जायेगा तो हम इसको कर देंगे ।

टर्न–3/शंभु/15.03.16

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0–1296/श्री केदार प्रसाद गुप्ता

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0–1297/श्री रामदेव राय

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0–1298/श्रीमती कुन्ती देवी

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । बाल विकास परियोजना, मोहड़ा एवं अतरी में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापन है । बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोहड़ा कार्यरत हैं जबकि जिला प्रशासन से प्राप्त सूचनानुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अतरी सम्प्रति चिकित्सकीय अवकाश में है।

बाल विकास परियोजना नीमचक बथानी में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापन तत्काल नहीं किया जा सका है।

वर्तमान में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोहड़ा को वैकल्पिक/स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अतरी एवं नीमचक बथानी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ताकि कार्य बाधित न हो।

तारांकित प्रश्न सं0–1299/श्री प्रमोद कुमार

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0–1300/श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन विद्यालय में 4 वर्ग कक्ष सही स्थिति में है।

2 एवं 3– वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन विद्यालय को भवन निर्माण हेतु पूर्व में कुल 26.00 लाख रूपया उपलब्ध कराया गया था। प्रश्नाधीन विद्यालयों के निर्माण हेतु आवंटित राशि का निर्धारित समय सीमा के अन्दर व्यय नहीं होने के कारण ए0सी0/डी0सी0 के सामंजन के क्रम में विभागीय निदेश के तहत कर्णांकित राशि संगत शीर्ष में वापस की गयी। राज्य संसाधन की उपलब्धता के उपरांत प्रश्नाधीन विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जायेगा।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : कब तक हो जायेगा ?

अध्यक्ष : पूछ रहे हैं कब तक हो जायेगा ?

श्री अशोक चौधरी : आने वाले वित्तीय वर्ष में सर ।

तारांकित प्रश्न सं0–1301/श्री महबूब आलम

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0–1302/श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

श्री चन्द्रिका राय : महोदय, यह प्रश्न नगर विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।

तारांकित प्रश्न सं0–1303/श्री अशोक कुमार

श्री अशोक चौधरी : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उच्च विद्यालय शिवाजी नगर एवं उच्च विद्यालय सिरोपट्टी खतुआहा चहारदिवारीयुक्त है। साथ ही उच्च विद्यालय शिवाजी नगर एवं उच्च विद्यालय सिरोपट्टी खतुआहा माध्यमिक विद्यालयों में सुदृढ़िकरण के क्रम में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया गया है।

शेष प्रश्नाधीन विद्यालयों के निर्माण हेतु आवंटित राशि का निर्धारित समय सीमा के अन्दर व्यय नहीं होने के कारण ए0सी0/डी0सी0 के सामंजन के क्रम में विभागीय निदेश के तहत कर्णांकित राशि संगत शीर्ष में वापस की गयी।

राज्य संसाधन की उपलब्धता के उपरांत शेष प्रश्नाधीन विद्यालयों में आगामी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण कराया जायेगा।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, पूरा बिहार पीने के पानी के संकट से गुजर रहा है। हमारा आग्रह होगा, कार्य–स्थगन प्रस्ताव हमारा है। महोदय, पानी का संकट खड़ा हो गया है। पहाड़ी इलाके में पानी मिल नहीं रहा है लोगों को और मैदानी इलाके में पानी का हाहाकार हो जायेगा। शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति ठप है, जल–मीनार सारे बंद पड़े हुए हैं, पूरे राज्य में हजारों चापाकल बंद हैं और आप क्वेश्चन आवर को प्राथमिकता दे रहे हैं। महोदय, आपसे आग्रह है कि हमलोगों ने जो कार्य–स्थगन प्रस्ताव लाया है उसको स्वीकृत कीजिए, बहस करवाइये और सरकार से जवाब करवाइये।

(व्यवधान)

महोदय, यह मामला प्रतिपक्ष का नहीं है, पूरे बिहार के करोड़ों लोगों का है। माननीय विधायकों के अधिकारों में सरकार कटौती कर रही है।

तारांकित प्रश्न सं0–1304/श्री मनोहर प्रसाद सिंह

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय, अस्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-455/प्रो0 दिनांक 03.03.2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कटिहार जिला के मनासाही प्रखण्ड अन्तर्गत मोहनपुर ग्राम पंचायत के वार्ड सं0-6 में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0-20 संचालित है एवं वार्ड सं0-6 के लाभार्थी आंगनबाड़ी केन्द्र से लाभान्वित हो रहे हैं।

तारांकित प्रश्न सं0-1305/श्री राजेश कुमार

श्री अशोक चौधरी : महोदय, अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड अन्तर्गत चिल्की अम्बा उच्च माध्यमिक विद्यालय अवस्थित है। विद्यालय में प्लस-टू का अध्यापन संचालित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वैसे मत कीजिए, जो टेबुल उल्टाइयेगा, यह गलत बात है।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : महोदय, पूरे बिहार में पानी का संकट है और पूरे बिहार की जनता में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गंगा किनारे के जिलों में पानी में आर्सेनिक पाया जा रहा है, उत्तर बिहार में आयरन पाया जा रहा है, दक्षिण बिहार में..... व्यवधान।

तारांकित प्रश्न सं0-1306/मो0 मुजाहिद आलम

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1, 2, 3 एवं 4- वस्तुस्थिति यह है कि अराजकीय प्रस्वीकृत मात्र (2459.1) कोटि के मदरसों के मामलों पर ही विचार करने का निर्णय लिया गया है। 2459.1 कोटि के मदरसों के संबंध में उनके प्रस्वीकृति अनुदान देने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। उक्त 2459.1 कोटि के मदरसों में 339 कोटि के मदरसा सम्मिलित नहीं है।

मो0 मुजाहिद आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ये जो 339 मदरसे हैं जो 1987 से ही एफ्लिएटेड हैं और 1987 से ही बच्चे मदरसा बोर्ड की परीक्षा में ऐपीयर हो रहे हैं । इसमें कार्यरत बहुत सारे शिक्षक रिटायरमेंट के ऐज तक पहुंच गये हैं। ये मदरसे भी 2459.1 कैटेगरी के मदरसों की तरह बिहार सरकार शिक्षा विभाग के संकल्प सं0-1090 की सारी शर्त्तों को पूरा करते हैं। इसलिए उनको अनुदान की श्रेणी में लाने की कृपा की जाय।

तारांकित प्रश्न सं0-1307/श्रीमती लेशी सिंह

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : महोदय, लोकतंत्र खतरे में है। हमें उम्मीद है आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, कार्य-स्थगन पर चर्चा करायेंगे, जवाब दिलायेंगे। यह मामला एक व्यक्ति का नहीं पूरे राज्य की करोड़ों जनता का है। सरकार बैठी हुई है, सरकार का जवाब हो । जल-मिनार को चालू कराया जाय, पेयजल की समस्या है। महोदय, आपसे आग्रह है कि कार्य-स्थगन को स्वीकार कीजिए। हमलोगों ने पेयजल संकट के लिए कार्य-स्थगन दिया है। राज्य में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है और सरकार गंभीर नहीं है। पानी का संकट दूर करने के बजाय सरकार जवाब से भाग रही है। राज्य में गर्मी शुरू हो गया और पानी का संकट गंभीर होता जा रहा है।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1309/श्रीमती गुलजार देवी</u>

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय,(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक- 345/जि0प्रो0, दिनांक 12.03.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड में 241 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है जिनमें 207 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। इनमें से 22 आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवन में, 20 आंगनबाड़ी केन्द्र नवनिर्मित भवन में एवं 165 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं जबकि 06 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माणाधीन है।

(2) स्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के प्रतिवेदनानुसार अंचल अधिकारी, मधेपुर ने 133 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने पत्रांक-1126, दिनांक 25. 10.2013 के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुर को सुपुर्द किया है तथा उक्त पत्र के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुर के पत्रांक 389, दिनांक 22.10.2013 के द्वारा भी कार्रवाई कर अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जा चुका है।

(3)महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली के पत्रांक D.O.No 11/145/2015-C.D.1 दिनांक 18-02-2016 के आलोक में MGNREGA के साथ Covergence कर चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न–4/अशोक/15.03.2016

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, मैंने आग्रह किया था सरकार को आपके माध्यम से कि राज्य में पेय जल का संकट है, पूरे राज्य में पेयजल का संकट व्याप्त है, पूरा पानी का लेयर भाग रहा है । महोदय, चापाकल बंद है.....

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण हाथ में प्लेकार्ड एवं नारा लगाते हुये सदन के वेल चले आये)

(व्यवधान)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–13(2) के तहत् बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–13(2) के तहत् बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 की प्रति को सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम– 2006 की धारा–11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 के तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन सभा मेज पर रखता हूँ ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण हाथ में प्लाकार्ड लिए हुये नारा लगा रहे थे । साथ ही श्री प्रेम कुमार, नेता प्रतिपक्ष भी अपने स्थान से लगातार बोल रहे थे ।)

(व्यवधान)

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान हेगा । इसके लिए 3(तीन) घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	-59 मिनट
जनता दल (यू)	-52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-39 मिनट
इन्डियन नेशनल कांग्रेस	-20 मिनट
सी.पी.आई.(एम.एल.)	-02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-02 मिनट
निर्दलीय	-03 मिनट ।

कुल- 180 मिनट

प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग आपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"ग्रामीण विकास विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 55,10,06,08,000/-(पचपन अरब दस करोड़ छः लाख आठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राजयपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य डा0 सुनील कुमार, श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री संजय सरावगी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री नीरज कुमार सिंह एवं श्री मिथिलेश तिवारी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

मा. सदस्य डा0 सुनील कुमार का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य डा0 सुनील कुमार अपना कटौती प्रस्ताव मूभ करें ।

मा. सदस्य डा0 सुनील कुमार अपना कटौती प्रस्ताव मूव करें ।

(डा0 सुनील कुमार के द्वारा कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ)

अध्यक्ष : कोई कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ । इसलिए मूल प्रस्ताव पर ही विचार-विमर्श होगा।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण हाथ में प्लेकार्ड लिए हुये नारा लगा रहे थे । साथ ही माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार, नेता प्रतिपक्ष भी अपने स्थान से लगातार बोल रहे थे ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार ।

श्री नीरज कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आदरणीय नीतीश जी, बाबु लालू प्रसाद जी, साथी तेजस्वी यादव जी एवं कॉंग्रेस पार्टी के संयुक्त प्रयास से महागठबंधन सरकार का गठन हुआ है । जब से इस सरकार का गठन हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैचेनी छाई हुई है । महोदय, सरकार के विधायी कार्यो में इनकी रूचि नहीं है । ये नहीं चाहते हैं कि गांव के गरीब और गांव का विकास हो । गांव के गरीब लोगों ने इनको नकार दिया है, गांव ने इनको खारीज कर दिया गया है, इनको बाहर निकाल दिया गया है महोदय ।

(व्यवधान)

ये लगातार सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते हैं विधान सभा में । इस बार पहली बार महागठबंधन की सरकार ने, 1 अप्रील से पूर्णतः गांवों में शराबबन्दी लागू कर दिया है और आने वाले दिनों में इनके जो झूठे वायदे हैं स्मार्ट सिटी बनाने का ,स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बार फिर सपने दिखाये जा रहे हैं, बिहार का एक भी शहर शामिल नहीं है और न राशि की ही व्यवस्था की गई है । लोगों का विश्वास इस सरकार पर मजबूत हुआ है । महोदय, साथी तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमलोगों ने युवा राजद के बैनर तले कार्यक्रम चलाया था, शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं विद्यालय चाहिए । महागठबंधन की सरकार आते ही उस पर अमल हुआ है । मैं श्रवण बाबू का आभार व्यक्त करता हूँ । भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं । महोदय, हमलोगों के युवा साथी उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में युवा राजद के माध्यम से हमलोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, युवा राजद के बैनर तले हमलोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, शराब नहीं किताब चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं विद्यालय चाहिये, महागठबंधन की सरकार आते ही उस पर अमल हुआ है महोदय । हम श्रवण बाबू, ग्रामीण विकास मंत्री के प्रति भी विशेष रूप से

आभार प्रकट करते हैं, उनके सफल नेत्त्व में, कुशल नेतृत्व में आदरणीय नीतीश कुमार जी साथ ही उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्रवण बाबू के कुशल नेतृत्व में गांव के तेजी से विकास हो, इसके लिए ये लगातार कार्य कर रहे हैं । लालू जी का प्रेम गांव के प्रति इतना था, जब सरकार थी तो अक्सर कहा करते थे कि गांय-भैंस चरती जाय, मुनिया बेटी पढ़ती जाय । हमारा गांव सुन्दर बने, स्वस्थ्य बने इस पर हमारी सरकार, हमारे नेता चिन्ता करते थे । एक बार फिर इस सरकार की जुमलेवाजी सामने आई है, उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनायेंगे , बिहार के लिए कोई भी व्यवस्था नही की गई, एक बार फिर बिहार के लोगों को झूठे सपने दिखलाये जा रहे हैं महोदय, लेकिन बिहार की जनता ने इनको पहचाना है और इनको खारीज किया है । जब 1990 में जब आदरणीय लालू प्रसाद के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, इन्दिरा आवास पहले कलस्टर में बना करता था किसी सरकार कर्मी के नाम से एग्रीमेंट करके उस समय इन्दिरा आवास का निर्माण कराया जाता था महोदय,

(व्यवधान)

आदरणीय लालू प्रसाद के नेतृत्व में, तत्कालीन केन्द्र सरकार में भागीदारी हुई महोदय, इन्दिरा आवास का आवंटन प्रति पंचायत 200 हो गया। आज क्या हालत है, यह सब के सामने है । आदरणीय लालू प्रसाद जी को जब जब बिहार की जनता ने ताकत दिया तब तब बिहार के गांव के लिए दिल खोलकर पैसे दिये गये । गरीब के हित में पैसे दिये गये । महागठबन्धन की सरकार आने के बाद उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री श्रवण बाबू के कुशल नेतृत्व में लगातार बिहार के गांव के हित में कार्य हो रहे है, चाहे वह जीविका हो, मनरेगा हो, चाहे इन्दिरा आवास हो, राज्य सरकार अपने संसाधन से योजनाओं का कार्यान्वयन करा रही है । महोदय पूर्व में जो व्यवस्था थी, पहले जो व्यवस्था थी मनरेगा में 90 केन्द्र सरकार देती और 10 हमलोग देते थे । आज स्थिति यह है कि 75:25 का कर दिया महोदय । क्रमशः

टर्न:5-15-03-2016- ज्योति

क्रमश:

श्री नीरज कुमार : महोदय, पूर्व में जो व्यवस्था थी उसके बदले आज मनरेगा में 75/25 की व्यवस्था की गयी है । जो पहले की व्यवस्था थी मनरेगा में 90 केन्द्र सरकार देती थी और 10 हमलोग देते थे । इन्दिरा आवास में भी वही हाल करके छोड़ा है एक तो पहले आवंटन घटाया महोदय , पहले 25/75 था और अभी 60/40 पर लाकर छोड़ दिया है । जीविका में भी वही हाल है । पहले 25/75 था अभी 60/40 का अंतर इन्होंने किया है । सारी योजना में यही किया गया है । ये जानते हैं कि गांव में हमारे हित के लोग नहीं है । ये गांव के खिलाफ हैं । ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनायें हैं उसके आवंटन को लगातार घटाया जा रहा है । इस गरीब राज्य के लिए, सरकार के लिए इतना संसाधन जुटाना जो गरीब राज्य है उसके लिए संभव नहीं है । महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में, आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में समेली और कुर्सेला को प्रखण्ड कार्यालय भवन का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है । जबकि प्रखण्ड का सृजन लगभग 21 साल पहले इन दोनों प्रखण्डों का आदरणीय लालू जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन कराया गया था । आजतक इसके कार्यालय सरकारी भवन में चल रहे हैं या फिर कोशी सिंचाई भवन में चल रहा है । समेली प्रखण्ड के अंतर्गत में एन0एच0-77 से नरहिया गांव से रामनगर होकर नदी के पार बारबीघापट्टी तक सड़क में पुल के निर्माण के लिए आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं । ये हमारी सरकार चाहती है लगातार गांवों में तीनों योजनाओं चाहे वह जीविका हो , इन्दिरा आवास हो उनमें तेजी से काम हो लेकिन इनको सरकार के विधायी कार्यों में व्यवधान करने के अलावा कोई काम नहीं है । लगातार जब सदन की शुरुआत हुई है लगतार सरकार के कार्यों में व्यवधान पैदा कर रहे हैं । महोदय, इनको कोई काम नहीं बचा है। साधारण सी बात को लेकर वेल में लगातार आते हैं । हम आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास का जो बजट है, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से आग्रह करेंगे कि जो केन्द्र का रेशियो है पहले की जो व्यवस्था थी 90/10 का चाहे वह इन्दिरा आवास हो, मनरेगा हो , जीविका हो वही पुरानी व्यवस्था पुन: दिलायी जाय। अगर इनको बिहार और इस राज्य की चिन्ता है महोदय, तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार आवंटन दिलाया जाय । स्पेशल कैटेगरी के माध्यम से और गांव का तेजी से जो शहरीकरण गांव के लोग तेजी से शहर की ओर सुविधाओं के लिए

जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है और 7 निश्चयों में वह शामिल है । सरकार हर बसावट तक बारहमासी सड़कों का निर्माण करना चाहती है ।

सरकार हर घर तक बिजली का कनेक्शन देना चाहती है । सरकार के 7 निश्चय में शामिल है । पीने का पानी, हर गांव में नल का पानी, हर बसावट में देने का सरकार का लक्ष्य है । भारतीय जनता पार्टी के साथियों को पच नहीं रहा है। महागठबंधन की नीति और सिद्धान्त को लेकर इनको बेचैनी है । आने वाले दिनों में ये लोग वापस फिर लौटकर नहीं आने वाले हैं । इस बेचैनी में इनको लगातार वेल में आने के पहले मीडिया में आने की चिन्ता रहती हैं । सरकार जिस हिसाब से गांव के लिए रचनात्मक काम लगातार कर रही है हम उसका स्वागत करते हैं और इस ग्रामीण विकास विभाग के बजट के समर्थन में हम खड़े हुए हैं और आपने बोलने का अवसर दिया हम आपके प्रति विशेष रुप से आभार प्रकट करते हुए अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ । जयहिन्द, जय बिहार ।

श्री निरंजन कुमार महतो : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आज सदन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका सहृदय से आभार प्रकट करता हूँ । साथ ही, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट जो पेश किया गया है, उसमें आय-व्ययक सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर ग्रामीण विकास विभाग पर हो रहे वाद-विवाद में सरकार के समर्थन में अपनी बातें बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कथन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन से करना चाहता हूं, उनकी सोच थी कि विकास का प्रारम्भ धरातल से होना चाहिए । प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य बने जो पूर्णतः आत्मनिर्भर हो, उसे किसी भी आवश्यकता को पूरा करने में किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, ऐसा आज मेरी सरकार द्वारा किया जा रहा है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय महागठबंधन के सहयोगी के साथ दिन-रात चिंतन किया करते हैं । माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में बिहार, भारत का विकसित राज्य बनने की दिशा में प्रयासरत है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना सदन में करना चाहता हूँ ।

बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीणों की गरीबी दूर करने, सुविधाओं को सुलभ एवं सुदृढ़ करने तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन

कर रहे लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है । गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धनों को इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ।

हर पंचायत में ग्रमीण आवास सहायक एवं पंद्रह पंचायतों पर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक तथा प्रत्येक प्रखंड में एक लेखा सहायक नियोजित किए गए हैं । नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल कौन्फ्रेंस आफ ई-गवर्नेन्स में बिहार राज्य को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, जो सभी बिहार राज्य वासियों के लिए गौरव की बात है ।

इन्दिरा आवास योजना से संबंधित सभी सूचनाओं को आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाता है जिससे पारदर्शिता बरकरार रहती है । ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को एनड्रोआयड आधारित मोबाइल फोन दिया गया है, जिससे वे अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारु रुप से कर सकें ।

श्री प्रेम कुमार : पानी का संकट है, सारे चापाकल बंद पड़े हुए हैं ।

अध्यक्ष : कम से कम माननीय सदस्य को तो अपनी जगह पर बैठा दीजियेगा तब बोलियेगा ।

श्री प्रेम कुमार : बैठा देंगे महोदय, आपसे आग्रह है कि सरकार को आप निर्देश दीजिये, राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या करेगी यह तो बताये ।

अध्यक्ष : आपके सदस्य आपको नहीं बोलने देना चाहते हैं । माननीय सदस्यों को जगह पर बैठाईये, हम आपकी बात सुनेंगे ।

श्री प्रेम कुमार : आपसे आग्रह है कि आप सरकार का वक्तव्य कराईये । बिहार में पानी का संकट है । सारे चापाकल बंद है ।

(इस अवसर पर श्री मो0 इलियास हुसैन से सभापति का आसन ग्रहण किया)

श्री निरंजन कुमार महतो : नागरिक सुविधा हेतु टोल फ्री नंबर की शुरुआत की गयी है जिसपर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं । विभागीय पदाधिकारी एवं गुणवत्ता मौनीटर्स के माध्यम से इंदिरा आवास आवंटन की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है ।

महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति में जो लोग हैं उनके लिए मुख्यमंत्री इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना चलायी गयी है । अगर समय पर लाभार्थी अपना आवास पूर्ण कर लेते हैं तो उन्हें दो हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है । राज्य में 101 सूचना प्राद्यौगिकी भवन, प्रखण्ड कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है । एन0पी0आर0 एवं

एस0ई0सी0सी0 डाटा को कर्ज कर सभी जिलों में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जन गणना का प्रारुप सूची का प्रकाशन करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है ।

महोदय, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करती है एवं गरीबों के अग्रसर विकास के लिए चिंतित रहा करती है ।

माननीय सभापति महोदय, मनरेगा एक केन्द्र सरकार की योजना है जिसे बिहार राज्य सरकार ने बखूबी क्रियान्वयन किया है । जहाँ केन्द्र सरकार न्यूनतम मजदूरी 162 रुपये तय की, वहीं राज्य सरकार 177 रुपये देने का काम कर रही है । मनरेगा के माध्यम से राज्य के सभी ग्रामीण परिवार को रोजगार दिया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्यान्वयन में खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा शिकायतों के निवारण के लिए राज्य स्तरीय शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण समिति का भी गठन किया है । मनरेगा जाँच दिवस के तहत माह के हर दूसरे एवं चौथे बुधवार को प्रत्येक प्रखण्ड के एक पंचायत में कार्यान्वित योजना की जाँच की जाती है । इ0एफ0एम0एस0 (इंटीग्रेटेड फंड मैनेजमेंट सिस्टम) द्वारा मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना में सीधे लाभुकों के खाते में पैसा भेजा जाता है ।

आधारभूत संरचना की विकास के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रत्येक गांव को जोड़ने का प्रयास चल रहा है, जिसमें काफी हद तक सफलता पायी जा चुकी है ।

हमारी सरकार कर्म में भरोसा करती हे इसलिए बातें कम करती है और विकास पर विशेष ध्यान देती है ।

माननीय सभापति महोदय, जैसे आजीविका चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है जो कि बिहार के हर एक गांव गांव तक पहुंचाया जा चुका है । जीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के जरिये गांव गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में राज्य सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ ।

क्रमशः

टर्न-6/विजय/15.03.16

(वेल में व्यवधान जारी)

श्री निरंजन कुमार मेहताः क्रमशः माननीय सभापति महोदय, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहे बिहार की सरकार को जितनी आर्थिक सहायता केन्द्र से मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है । वर्तमान में बिहार सरकार ने सरकारी सेवाओं में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण कर समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास

किया है । इसकी जितनी तारीफ की जाय वह कम होगी, अगर महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा और परिवार सशक्त होगा तो विकास की सीढ़िया चढ़ना आसान हो जायेगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन में केन्द सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास योजनाओं में सहयोगी की भूमिका निभायें । भारत सरकर द्वारा केन्द्र की सभी योजनाओं में कटौती की जा रही है, चाहे इंदिरा आवास योजना हो, मनरेगा हो, आजीविका हो सभी में केन्द्र द्वारा राशि की कटौती की जा रही है । सारा बोझ राज्य सरकार पर डाल रही है इलिए विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों से निवेदन है कि केन्द से मिलकर बिहार को कटौती राशि देने का वकालत करें जिससे भारत सरकार, अगर बिहार को कटौती राशि देती है तभी बिहार का विकास संभव है । हाल ही में दिनांक 12.03.2016 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हाजीपुर के छौकिया सभा में अपने वक्तव्य में स्वीकार किये हैं कि बिहार के विकास के बगैर भारत विकसित देश नहीं बन सकता भारत का भाग्य बदलने के लिए पहले बिहार का भाग्य बदलना होगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि विकास की शुरूआत नीचे स्तर से ही करना चाहिए क्योंकि भारत गांवों का देश है । जहां लगभग 70 प्रतिशत लोग गांव में बसते हैं, अगर उनका सही रूप से विकास हो तभी सही मायने में भारत विकसित कहलाएगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बिहार सरकार को और ग्रामीण विकास विभाग को जो कि 24 घंटे दिन-रात जनता के विकास में प्रयासरत है । यह सराहनीय एवं धन्यवाद के पात्र हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं पुन: आपका आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

जय हिन्द, जय बिहार, जय महागठबंधन । धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मा0 सदस्य, श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार द्वारा दिये गये प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । विकास हमारा प्रारंभिक उद्देश्य है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): अरूण बाबू कृपया शांत रहें । नेता, विरोधी दल से मैं जानना चाहता हूं कि यह कोलाहल किस बात की है । ऐसा कोलाहल क्यों ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मनोहर जी आप बोलें ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने विकसित देश की परिभाषा देते हुए कहा है कि " एक विकसित देश वह होता है जो अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पर्यावरण में स्वतंत्र और स्वस्थ्य जीवन का आनन्द लेने का अवसर देता है ।"दुनिया के गरीब देशों की गरीबी दूर करने का उपाय ढूंढने के लिए 2000 में न्यूयार्क में यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित मिलेनियम सम्मेलन में 2015 तक विश्व की गरीबी को आधी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । गरीबी दूर करने के उद्देश्य से योजना आयोग द्वारा गठित तेन्दुलकर समिति ने 55.5 प्रतिशत ग्रामीण और 43.07 प्रतिशत शहरी आबादी को बी0पी0एल0 की श्रेणी में रखा ।

सभापति महोदय, सर्वविदित तथ्य है कि भारत गांवों का देश है । गांवों के विकास के बिना किसी भी पक्कार के विकास की बात अधूरी होगी । ग्रामीण इलाकों में सड़कों का अभाव है । वर्षा और दैनिक जीवन में उपयोग में लाये गये जल के बहाव का उचित प्रबंध नहीं है । सड़के नहीं हैं । हैं भी तो कच्ची हैं । वर्षा के समय जीवन नारकीय हो जाता है । खुले में शौच की विवशता है । रोशनी का प्रबंध नहीं है ।

सभापति महोदय, 83 वर्ष में पहली बार सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत के रूप में सम्पन्न जनगणना के 2011 में प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार देश में कुल 24.39 करोड़ परिवारों में से ग्रामीण भारत में 17.91 करोड़ परिवार आते हैं । ग्रामीण भारत के 75 प्रतिशत लोग यानी 13.34 करोड़ परिवार की मासिक आय 5 हजार रूपये से कम है । गांवों में 10 हजार से अधिक आय वालों की संख्या मात्र 8 प्रतिशत है । गांव में रहने वाले परिवारों में 10.69 करोड़ वंचित परिवार हैं । इनमें से 5.37 करोड़ परिवार भूमिहीन हैं ।2.5 करोड़ परिवार एक कमरे के कच्चे मकान अथवा झोपड़ी में गुजर करते हैं । गांवों में 3.86 करोड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति परिवार के लोग रहते हैं । बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.58 प्रतिशत है । बिहार में 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की मासिक आय 5 हजार और उससे भी कम है । 15 प्रतिशत ग्रामीण खुले आसमान में खाना

बनाते हैं । 65.64 प्रतिशत परिवारों के लिए जल निकास की व्यवस्था नहीं है । 80 प्रतिशत लोग शौचालय विहीन हैं ।

सभापति महोदय, बेरोजगारी और असमानता की उग्रता में कमी को ही नि:संदेह के विकास का पैमाना माना जाता है । गांवों की असुविधाओं, विवशताओं और कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने सात निश्चयों में से एक निश्चय ग्रामीण इलाकों में जनसुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा हे । जलापूर्त्ति, स्वच्छता, सीवरेज, वर्षा जल की निकासी, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, सड़कों पर रोशनी, सड़कों, पैदल पथों का निर्माण, पार्क का निर्माण, खेल के मैदानों का निर्माण, कब्रिस्तान एवं श्मशान के सुदृढ़ीकरण और रख रखाव के लिए 14वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि को प्रतिवर्ष प्रत्येक पंचायत को 43 लाख रूपये प्रदान करने की योजना है । मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत हर प्रखंड में पांच गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जायेगा । हर चयनित बसावट को अतिरिक्त 10 लाख रूपये की राशि देने का निणर्य लिया गया है । प्रखंड स्तर पर इसके नोडल पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाये गये हैं ।

क्रमश:

टर्न–7/बिपिन/15.3.2016

(व्यवधान)

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: क्रमश: महोदय, गरीबी दूर करने में सबसे अधिक उपयोगी कार्यक्रम मनरेगा योजना है । यह कार्यक्रम लोगों की आमदनी बढ़ाने और मजदूरों के पलायन रोकने में अधिक कारगर साधन सिद्ध हो सकता है । राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी 177रूपया निर्धारित की गयी है । केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 162 रू0 निर्धारित है । बिहार सरकार द्वारा दिसम्बर 2015 तक 3करोड़ 52लाख 69हजार मानव दिवस सृजित किये गये और 10अरब 14करोड़ 42लाख रूपये का व्यय हुआ । केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 10.50लाख श्रम दिवस की स्वीकृति दी है ।

(व्यवधान)

महोदय, सरकार ने प्रत्येक पंचायत और प्रखण्ड में मनरेगा भवन बनाने का निर्णय लिया है । सचिवालय के रूप में कार्यरत इस मनरेगा भवन में काम के इच्छुक लोग अपना नाम प्रविष्ट करा सकते हैं । मनरेगा के कार्यों में गड़बड़ी रोकने के लिए सामाजिक अंकेक्षण द्वारा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने की योजना है ।

(व्यवधान)

मनरेगा योजना कार्यक्रम सर्वाधिक विवादित एवं आलोचना का क्षेत्र रहा है । व्ययित राशि के अनुपात में कम कार्य किया जाना, कार्य नहीं किये जाने के बाद भी राशि की निकासी, मजदूरों के जॉबकार्डों का ठीकेदारों द्वारा मनमाना उपयोग, कार्य करा दिये जाने के बाद राशि का भुगतान नहीं किया जाना, अनावश्यक स्थान में योजना का क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण कार्य का अभाव इत्यादि कई तरह के आरोप प्राय: लगते रहे हैं ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, बैठ जाइए ।

राष्ट्रीय जनता दल- श्रीमती रेखा देवी । सात मिनट आपको बोलना है ।

(व्यवधान)

श्रीमती रेखा देवी: माननीय सभापति महोदय, आज मैं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत मॉग अनुदान के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): यह अशोभनीय है । माननीय नेता विरोधी दल, यह सब अशोभनीय है । शांति बनाए रखें । शांति। शांति से ही समस्या का निदान होगा ।

(व्यवधान)

श्रीमती रेखा देवी: महोदय, भारत गॉवों का देश है और बढ़ती शहरीकरण के बावजूद देश की बड़ी आबादी लगभग गॉवों में निवास करती है और गॉवों के समग्र विकास के बिना देश और प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है । महोदय, बिना ग्रामीण विकास के जीवन के भौतिक गुणवत्ता में पूर्ण सकारात्मक परिवर्त्तन को सूचित करता है और इस सकारात्मक परिवर्तन में आर्थिक और सामाजिक दोनों पक्ष शामिल है । विकास का मतलब महोदय, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य संपूर्ण, भौतिक जीवन, उचित आवास और कल्याणकारी सामाजिक संसाधनों के द्वारा गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर ऊॅचा करना है । महोदय, माननीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों, दलितों, पिछड़ा, दबे-कुचले को बोलने का अधिकार दिये हैं । जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने दलित, दबे-कुचले लोगों को विकास के राह पर लाने का दृढ़ संकल्प लिये और उन्हीं के माध्यम से सभी ग्रामीण जनता को जागरूक करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने किये । समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को जब तक सामाजिक,

शैक्षणिक और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत, सशक्त नहीं बना लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे । इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार सरकार तथा ग्रामीण विकास विभाग कृत संकल्प है । माननीय सभापति महोदय, ग्रामीणों का विकास हमलोगों की पहली प्राथमिकता है और हमलोग इसके लिए कटिबद्ध हैं । आज जिस तरह से गांव में इस सरकार के द्वारा बिजली को विकसित करने का काम किया गया है, वह काबिले-तारिफ है । गांव के नाली-गली एवं तालाब पइन, अन्य मुख्य सुविधाओं पर भी विचार किया जाना चहिए । महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है । यहां की आबादी लगभग कृषि पर आधारित है । कृषि को बेहतर बनाने के लिए नहर, ट्यूब वेल एवं समय पर किसानों को बीज खाद एवं रसायनिक पदार्थ की आवश्यकता है । सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, उस क्षेत्र में ज्यादातर नहर की व्यवस्था नहीं है । किसानों को उनकी मुख्य सुविधा में, इस सरकार में आशा एवं विश्वास करती हूँ कि हमारे क्षेत्र के साथ-साथ पूरे बिहार के किसानों को यह मुख्य सविधा मुहैया कराई जाए ताकि मेरे क्षेत्र के साथ-साथ बिहार के किसान भी खुशहाल रहें ।

(व्यवधान)

माननीय मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि छोटे-छोटे गांवों एवं बसावट को भी इस येजना के अंतर्गत जोड़ा गया है जिसे लोगों को आज काफी सहुलियत हो रही है । मुख्य सड़क आने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है । इनका कार्य सराहनीय एवं प्रशंसनीय है । मैं पटना जिला अंतर्गत मसौढ़ी विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आई हूं ।

माननीय सभापति जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कृषि के लिए हो रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु दरघा नदी पर बराज का निर्माण कराने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत दिनों से चल रही है । मेरी आग्रहपूर्वक निवेदन है कि दरधा नदी पर बेरा में बराज का निर्माण कराया जाए जिससे कि किसानों के खेतों में समुचित पानी मिल सके जिससे पटवन का काम आसानी से होगा और किसान खुशहाल होंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सभापति जी से यह भी निवेदन करना चाहूँगी कि आज पूरे प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों को इंदिरा आवास लाभ दिया जाता है लेकिन भारत सरकार की नजरअंदाजी की वजह से वित्तीय वर्ष 2015-16 समाप्ति पर है, लेकिन अभी तक इंदिरा आवास के लाभुक को बैंक के खाते में राशि नहीं दी गयी है जिसके कारण गरीब परिवारों में भारी असंतोष है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन

करती हूं कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के इंदिरा आवास के लाभुकों को जल्द-से-जल्द इंदिरा आवास का लाभ दिया जाय ताकि गरीब परिवार अपना इंदिरा आवास का निर्माण कार्य, अपना रहन-सहन ठीक कर सके ।

माननीय सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पेंशनधारियों को पेंशन की लाभ दी जाती है जबकि पूरे प्रदेश में पेंशन का भुगतान जुलाई 2015 तक ही की गयी है, शेष महीनों का पेंशन भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है ।

(व्यवधान)

भारत सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि पेंशनधारियों के पेंशन का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा जबकि पेंशन का लाभुक वृद्ध, विकलांग एवं विधवा होते हैं । वृद्ध एवं विकलांगों को बैंक में आने-जाने में काफी कठिनाई होती है । इसके कारण उनके बैंकों में खाता नहीं खुल पा रहा है । अगर खाता खुलवा ली जाती है तो प्रत्येक माह में वृद्ध एवं विकलांग द्वारा प्रतिमाह बैंक जाकर पेंशन की राशि लाना संभव नहीं है ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो.इलियास हुसैन): माननीय सदस्या श्रीमती रेखा देवी, आपका समय समाप्त हो गया।

जनता दल(यू) के डा0 विनोद प्रसाद यादव ।

(व्यवधान)

टर्न-8/राजेश/15.3.16

(व्यवधान)

श्री विनोद प्रसाद यादव - सभापति महोदय, आज सदन में प्रस्तुत ग्रामीण विकास विभाग की मांग के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, ग्रामीण विकास विभाग गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत 89 प्रतिशत जनता गॉवों में निवास करती है .....(व्यवधान)

उनलोगों का देख-भाल ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा होता है लेकिन हमारे विरोधी दल के जो भाई है, अगर इस विभाग पर चर्चा करते, तो हमलोगों को भी अच्छा लगता, ये गरीबों की बात उठाते और गरीबों के लिए जो मनरेगा योजना चल रही है, उसके बारे में सुझाव देते, जैसे गरीबों के लिए जीविका योजना चल रहा है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, उसके संबंध में अपना सुझाव देते, इंदिरा आवास

योजना जो गरीबों के लिए चल रहा है, अगर उसके संबंध में ये लोग सुझाव देते, तो बहुत बेहतर होता लेकिन आज जो इनकी हरकत है .....(व्यवधान)
उसको बिहार की जनता देख रही है, सारे बिहार की जनता और देश की जनता आज देख रही है कि गरीबों के सवाल पर ये लोग किसतरह से सदन को बाधित करना चाहते है, इनको गरीबों से कुछ लेना-देना नहीं है, ये लोग सिर्फ गरीबों के वोट के प्यासे हैं लेकिन उनके विकास से इनलोगों को कोई लेना देना नहीं है, आज जब ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है, इससे पहले जिस इशू को ले करके आज सदन को ये लोग बाधित कर रहे हैं, उसका मांग पहले आया था महोदय, अगर पी0एच0ई0डी0 की मांग पर, ये लोग अपने सुझाव को रखते, तो हमें लगता कि इसका निदान उस दिन ही हो जाता लेकिन इनलोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, ये लोग पेयजल के प्रति संजीदा नहीं है, आज इनके हरकत को देख करके मुझे एक बात याद आती है, एक आदमी आता है और पूछता है कारोबार के बारे में, तो वह कारोबारी कहता है कि हम अंधो के शहर में आये है, ठीक उसीतरह से ये लोग आज जब ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा हो रही है, तो ये लोग पेयजल की बात को उठा रहे हैं, अगर ये लोग ग्रामीण विकास विभाग की बात पर अपना सुझाव देते, तो बेहतर होता लेकिन इनलोगों को तो गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है, इस विभाग से गरीबों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है, गरीब मजदूरों को रोजगार मिलता है लेकिन भारत की सरकार मनरेगा की राशि में कटौती कर रही है.....(व्यवधान)
भारत सरकार मनरेगा कार्यक्रम को बाधित करना चाह रही है, इनलोगों को गरीबों से कोई लेना-देना नहीं है, यह योजना सीधे गरीबों से जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, हमारे मजदूर भाई जो पहले राज्य से बाहर जाते थे कमाने के लिए, उनको हमारी सरकार ने 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देने का काम किया, जिससे उनके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है महोदय, बिहार सरकार गरीबों के हित की बात करती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, गरीबों की भलाई चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ भारत की सरकार जो दिल्ली में बैठी है, उनको गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है, गरीबों के प्रति कोई उनका रुझान नहीं है, वे चाहते हैं कि गरीब लोग सदा गरीब ही रहे, ये लोग गरीबों के बिल्कुल विरोधी लोग है, महोदय, हमने देखा है कि हमारे माननीय मंत्री जी प्रत्येक जिला में जाकर मनरेगा की समीक्षा कर रहे हैं कि मनरेगा के तहत गरीबों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं और जिस जिले में प्रगति कम थी, वहाँ पर प्रगति लाने का काम किया, हमारे माननीय मंत्री जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, कैसे हम गरीबों को खुशहाल बनायेंगे,

हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए कृतसंकल्पित है बिहार में, मैं माननीय मंत्री जी को मनरेगा के संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूँ कि 60-40 का जो प्रतिशत है मनरेगा योजना में, उसमें मिट्टी का काम बहुत कम गया है, इसलिए उस कार्य को जमीन पर लाने के लिए खेतिहर मजदूरों को भी मनरेगा से जोड़े, किसानों को मनरेगा से जोड़े और किसान जो मजदूर के सामान किसान हैं, जो अपने से खेती करते हैं, उनको मनरेगा योजना में शमिल करके किसानों की भी स्थिति को मजबूत करें, तब मनरेगा योजना कामयाब होगा। महोदय, मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, जो इसको सतह तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कामयाब हो लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे विपक्ष के भाई है, उनको मनरेगा योजना सफल हो, ना हो, इससे इनको कोई चिंतन मनन की जरुरत नहीं है, इनको गॉवों के गरीबों से कोई लेना-देना नहीं है और भारत सरकार से जो पैसा मनरेगा के तहत आना चाहिए, आज हमारे गरीब मजदूर महीनों-महीनो इंतजार करते हैं भुगतान का लेकिन भारत सरकार आज उन मजदूरों का ख्याल न करके कुंडली मार कर बैठी रहती है, मजदूर अपने पैसों के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाते रहते हैं और हमारी सरकार उनसे पैसों की मांग करते रहती है लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है महोदय, तो मैं यही कहूंगा कि मनरेगा योजना को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार मनरेगा योजना में जितना बजट है, उसके आलोक में राशि उपलब्ध करावें, हम इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं और हमारे माननीय मंत्री जी कृतसंकल्प है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चय को लागू करने के लिए, ये बराबर मनरेगा योजना की समीक्षा करके इसको सुदृढ़ करे और गरीबों को रोजगार मिले, इसके लिए काम करें.....

(व्यवधान)

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत जीविका चल रही है और इंदिरा आवास, तो जीविका और इंदिरा आवास के संबंध में कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब चल रहे थे वोट मॉगते, तो जनता के सामने उन्होंने वादा किया था कि हम एक-एक लोगों को घर में रहने के लिए आवास उपलब्ध करायेंगे, एक-एक लोगों को आवास अपना होगा लेकिन जब उन्हें सत्ता मिली देश की, तो वे गरीबों का हाल भूल गये, गरीबों से उनका नाता टूट गया ..... (व्यवधान)

महोदय, गरीब लोग गर्मी में तो अपना दिन बिता लेते हैं लेकिन जब बरसात का दिन आता है और जब उनके झोपड़ियों से पानी टप-टप चूता है, तो वे अपने बाल-बच्चों के सर को छुपाने के लिए दूसरे जगह की तलाश करते हैं, बच्चों

को लेकर जाते है लेकिन उन गरीबों के बारे में ये क्या करते हैं, इन्होंने इंदिरा आवास गरीबों से छीन लिया, मैं दो शब्द उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि:-"दिखाया था सुनहरे सपने दीन-हीन का, लेकिन वे सपने चूर-चूर हो गये,

सताना अच्छा नहीं होता दीन-हीन का, छीन लिया गरीब बेसहारों का घर,

सपना दिखाकर अच्छे दिन का, अच्छे दिन का" .....(व्यवधान)

लेकिन इनलोगों ने उन गरीबों को अच्छे दिन दिखाकर उनसे आवास भी छीन लेने का काम किया। महोदय, जब 2014 में यू0पी0ए0 की सरकार थी, तो 6 लाख 5 हजार इंदिरा आवास बिहार को मिलता था लेकिन जब ये लोग सत्ता में आ गये, तो इनलोगों ने इंदिरा आवास के टारगेट को दो साल में घटाकर 2 लाख 45 हजार कर दिया, यह कैसा गरीबों के साथ इनका इंसाफ है, ये गरीबों के साथ नाइंसाफी करने वाले लोग हैं, ये लोग गरीबों को सताने वाले लोग हैं, ये लोग केवल गरीबों का वोट चाहने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं को हल करने से इनको कोई लेना-देना नहीं ई, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि:- ..... (व्यवधान)

" गरीब सताये तीन गये, धन, वैभव और वंश,
ना मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस ।"

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन):- बहुत अच्छा।

श्री विनोद प्रसाद यादव:- तो महोदय, जो गरीबों को सताता है, उसका सफाया निश्चित होता है। क्रमश:

टर्न-9/कृष्णा/15.3.16

श्री विनोद प्रसाद यादव (क्रमश:) महागठबंधन के लोगों को असीम समर्थन दे करके इनको सबक सिखलाने का काम किया है । महोदय, उसके बाद भी ये सोचनेवाले और समझनेवाले नहीं हैं । ये बड़े लोगों के संरक्षक हैं, ये कॉरपोरेट लोगों के संरक्षक है। बेचारा गरीब आवास के लिये दर-दर की ठोकरें खा रहा है । उनकी चिन्ता इनको नहीं है । इन्दिरा आवास में 75 परसेंट राशि भारत सरकार देती थी लेकिन गरीबों के साथ नाइन्साफी करने का काम किया, इन्होंने उस राशि को घटा करके आधा कर दिया । यह गरीबों के साथ सरासर नाइन्साफ है । गरीब इनका समय गिन रहे हैं । 2019 का इंतजार कर रहे हैं गरीब लोग । एक-एक बात का बदला गरीब लोग इनसे लेंगे और आगे भी लेने काम करेंगे । महोदय, इनकी सरकार जो गरीबों के वोट से बनी लेकिन ये नीतियां बनाने के लिये नागपुर के आर0एस0एस0 के कार्यालय में शरण लेते हैं और आर0एस0एस0 के कार्यालय से जो एजेंडा पास

करके मिलता है, उसी एजेंडे को देश में लागू करने का काम करते हैं । इसलिए ये लोग गरीब के हित में कभी भी काम करनेवाले नहीं हैं । गरीबों के बिल्कुल ही विरोधी लोग हैं । हमलोग देखते हैं कि ये लोग महोदय, आपका लाल बत्ती का इशारा हो रहा है तो मैं चंद शब्दों में जीविका के संबंध में कहना चाहता हूं । जीविका की महिलायें ग्रामीण विकास के तहत अच्छी काम कर रही हैं । जीविका के तहत महिलायें स्वावलंबी हो रही हैं । पहले लोग कहते थे कि औरतें केवल खाना बनाने के लिये ही होती हैं लेकिन आज औरतें रोजगार पैदा कर रही हैं । महिलायें जीविका के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को नशामुक्त क्षेत्र बनाने का घोषणा किया है उस पर जीविका की महिलायें घुम-घुम करके नशामुक्त बिहार बनाने के लिये काम कर रही हैं । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ये लोग भी उस अभियान में शामिल हों ।

(व्यवधाान जारी)

आज महिलायें गांव-गांव घुम-घुम कर कह रही हैं कि आओ मिलकर हाथ बढ़ायें, नशामुक्त बिहार बनायें । जय हिन्द, जय बिहार ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : धन्यवाद, धन्यवाद । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय सदस्य श्री मदन मोहन तिवारी ।

श्री मदन मोहन तिवारी : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है, जहां से हमारे देश और प्रदेश का भोजन एवं खाने की हर सामग्रियां प्राप्त होती है । हमारे प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अनेक योजनायें चलायी जा रही है । जैसे मनरेगा योजना, बी0आर0जी0एफ0 योजना, इन्दिरा आवास योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना । व्यवधान

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य बोलिये,बोलिये ।

श्री मदन मोहन तिवारी : मुख्यमंत्री संपर्क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, महोदय, इन योजनाओं में भारत सरकार के द्वारा उदासीनता के कारण बी0आर0जी0एफ0 योजना को बंद कर दिया गया है, जिससे हमारे गांवों में महादलित, अतिपिछड़े के टोलों में नाली एवं शौचालय नहीं बन रहे हैं । यह बहुत ही खेद का विषय है । महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में तत्कालीन प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी, श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के समय में भारत सरकार के द्वारा 80 प्रतिशत राशि राज्यों को दी जाती थी जो आज की तिथि में हमारे प्रधान मंत्री जी ने 60 और 40 का हिस्सा लगा दिया जिससे हमारे ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनने में अवरोध पैदा हो गया है । यह बहुत ही खेद का

विषय है । महोदय, इसी तरह से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना से बदल कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कर दिया गया, जिसमें बिहार को आधा की हिस्सेदारी दी गयी, जिससे कार्य कराना संभव नहीं हो पा रहा है । यह भी बहुत खेद का विषय है । महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा गांव के वासियों के लिये अन्नपूर्णा योजना, निशक्त योजना, वृद्धा पेंशन योजना, बालिका विवाह योजना सरकार के द्वारा चलायी जा रही है, जो काफी सराहनीय है । सरकार के 7 निश्चय ग्रामीण विकास विभाग अनेक कार्यों से जुड़े हुये हैं । जैसे - गलियों का पक्कीकरण करना, नाली का निर्माण करना, हर घर को नल देना, हर घर को बिजली देना, महिलाओं को 35 परसेंट आरक्षण देना, युवाओं को क्रेडिट कार्ड देना और बेरोजगारों को एक हजार रूपया दो सालों तक पेंशन देना । यह भी बहुत सराहनीय कार्य है ।

महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र के प0चम्पारण में बहुत ऐसे बसावट हैं, जहां ब्रीक सोलिंग के अभाव में आज भी लोगों को कच्ची सड़कों पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है । इन गांवो में मंझरिया सेठ, परसा, माधेपुर, मलाही टोला आदि हैं । आज के दिन में भारत सरकार के द्वारा योजनाओं में कटौती एवं बिहार के प्रति उदासीनता से बिहार का विकास करने में राज्य को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । यह बहुत ही खेद का विषय है । महोदय, आज के समय में केन्द्र सरकार के द्वारा इन्दिरा आवास में बराबरी का हिस्सा कर देने से गांवों के गरीबों को आवास बनाने में काफी कठिनाई हो रही है । यह भी बहुत खेद की बात है । हमारे जिला में बेतिया शहर के बगल से चन्द्रावत नदी है, अगर इसका जीर्णोद्धार कर दिया जाता है तो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जल-जमाव की समस्या समाप्त हो सकती है । महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : और बोलिये ।

व्यवधान

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अनेक विकासात्मक कार्य हो रहे हैं । मेरे जिला में कल-परसों गोपालगंज-बेतिया के बीच जो पुल बना है, वह काफी सराहनीय बात है । यह गौरव की बात है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भारत सरकार के सहयोग के बिना अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ।

धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : जनता दल (यूनाईटेड) माननीय सदस्या श्रीमती कविता कुमारी जी ।

श्रीमती कविता कुमारी : सभापति महोदय, आज मैं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत 55 अरब, 10 करोड़, 6 लाख, 8 हजार के बजट स्वीकृति के पक्ष में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं । हमारे देश के ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं । देश की आत्मा गांवों में बसती है । अगर गांवों का विकास होता है तो देश तरक्की करता है और अगर गांवों का विकास नहीं होता है तो देश पिछड़ेपन की स्थिति में आ जाता है । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें ग्रामीण जनता की कठिनाईयों का समाधान होता है । महोदय, बिहार की जनता की पुकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो सभी के दुख-दर्द को समझते हैं ।

(व्यवधान जारी)

महोदय, हमारी जो सरकार बनी, चुनाव के समय तरह-तरह के आडम्बर किये गये, तरह -तरह के प्रलोभन दिये गये, उसको काटते हुये हमारे बिहार की जनता ने सही और कर्मपुरूष श्री नीतीश कमार जी को चुना। जिस प्रकार मोदी जी ने बिहार की जनता को अपमानित करने का कार्य किया।

क्रमशः :

टर्न-10/सत्येन्द्र/15-3-16

(व्यवधान)

श्रीमती कविता कुमारी(क्रमशः):महोदय,हमारी सरकार की मंशा है कि सभी ग्रामीण जनता का कल्याण हो इसके तहत महोदय,14वीं वित्त आयोग की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा निश्चित मूलभूत सेवाओं पर भी किया जायेगा। इसके तहत ग्रामीण अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आजीविका हेतु जन उपयोगी योजनाओं का भी चयन कर सकते हैं। महोदय,कृषि क्षेत्र में फलदार वृक्षों का रोपण,पोखर, तालाब, कुओं का निर्माण,बर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जायेगा। महोदय,हमारी सरकार इस योजना के तहत हर घर तक नल द्वारा पेयजलापूर्त्ति, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, पक्के नालों का निर्माण आदि कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सभापति महोदय,बुनियादी सुविधाएं, इसके तहत सड़क, पैदल पथ,पुल पुलिया एवं खेल का मैदान, टोला सम्पर्क पथ का निर्माण एवं रखरखाव पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की जायेगी। महोदय,केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार बिहार को परेशान करने का कार्य किया जा रहा हैं। महोदय विगत चुनाव में जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा हमारे

क्षेत्र में तरह तरह के भ्रम फैलाये गये। उन्होंने जो प्रत्याशी खड़े थे उनके फेवर में उन्होंने कहा कि वह मेरा धर्मपुत्र है लेकिन बिहार की जनता धर्मपुत्र को पहचानती है काम करने वालों को ही अपना कार्य करने के लिए सौंपती है,धर्मपुत्र की यहां आवश्यकता नहीं होती है। महोदय,इसी तरह हमारी सरकार का लक्ष्य है कि कब्रिस्तान,श्मशान में चाहरदिवारी आदि का रखरखाव करें। महोदय,महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने राज्य के सभी निर्धन परिवार के महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पशुधन,खाद-बीज विषयक (व्यवधान जारी)से जोड़ने एवं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का दृढ़ संकल्प लिया है। इससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होगीं और परिवार के खर्च में अपना योगदान देंगी। महोदय, केन्द्र सरकार राज्य सरकार के 7 निश्चय के तहत आजीविका एवं पी0एच0ई0डी0 के साथ-साथ सहभागिता के आधार पर राज्य के 10 जिलों के 24 प्रखंडों के 64 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसके तहत अनेकों प्रकार का कार्यक्रम अभियान चलाये जा रहे हैं। महोदय,हमारी सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों एवं अन्य सभी प्रकार के भुगतान इलेक्ट्रोनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा मजदूरों के खातों में किया जायेगा ताकि बिचौलिये इसका लाभ नहीं उठा सकें। महोदय,हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी -

हार नहीं मानूंगा दूर तलक जाऊंगा,
आसमां के ऊपर अपना आशियां बनाऊंगा।

महोदय,इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। चूंकि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी अभी आज ही बजट पेश हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि हमारे क्षेत्र में बगौरा शिवाला से लेकर कोरर म0 विद्यालय तक का सड़क अत्यंत जर्जर है उस जर्जर सड़क को कृपया आप निर्माण जरूर करायें ताकि वहां की जनता को आने-जाने में कठिनाईयों का जो सामना करना पड़ता है उसका सामना न करना पड़े। महोदय, जीविका के माध्यम से सभी महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह चलाकर उनका गठन करके सभी को प्रशिक्षण देकर के उनको कार्य करने के अनुरूप बनाया जा रहा है। मैं सरकार से आपके द्वारा आग्रह करूंगी कि हमारे क्षेत्र में भी महिलाओं के रोजगार के लिए जो हसनपुरा प्रखंड में (व्यवधान जारी)कम से कम चार-जगहों पर स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाय ताकि वहां की महिलाएं को अपने गृह उपजार्जन के लिए,जीविकोपार्जन के लिए अपना कुछ

आर्थिक उन्नति हो। महोदय, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आती है और हमसे कहती हैं कि पहले तो हम खेतों में हम काम करते थे इसलिए हमको कुछ मजदूरी मिल जाता था लेकिन खेती का कार्य आधुनिक यंत्रों द्वारा करने के कारण हमको वह लाभ नहीं मिल पाता है इसलिए महोदय से आग्रह है कि उन महिलाओं के हित को देखते हुए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाय और भी जो प्रशिक्षण जो महिलाएं करती है उनको दिया जाय ताकि वो अपना कार्य कर सके और परिवार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। महोदय,मैं कहना चाहूंगी कि दृढ़ निश्चय के साथ बिहार विकास के लिए खड़ा है–

जो खड़ा रहा अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में,
मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में।

महोदय,इसी के साथ आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया। महोदय,ग्रामीण विकास विभाग बहुत ही दूरदृष्टि रखता है बिहार की उन्नति के लिए बिहार के विकास के लिए उसके तहत विभिन्न गांवों में अभी शौचालयों की जो स्थिति है पूरी तरह बन नहीं पाया है। उस स्थिति को सुधारने के लिए वहां के पदाधिकारियों को और ट्रेनिंग करने की जरूरत है ताकि वो निश्चित रूप से जो उस कार्य में कमी आ रही है देरी हो रहा है वो जल्द से जल्द हो ताकि हमारी सरकार का जो निश्चय है, 7 निश्चय कि हम स्वच्छता लायेंगे, नालों का निर्माण करेंगे, पक्कीकरण करेंगे ताकि समाज के जो लोग हैं उनको किसी समस्याओं का सामना नहीं करना पडे। इस समस्या को ध्यान में रखना होगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। महोदय, विपक्ष के लोगों द्वारा बार–बार जनता की समस्याओं को दरकिनार कर के झूठी पब्लिसिटी के लिए यहां वेल में आकर और आगे जाकर मीडिया में अफवाह फैलाने के लिए कार्य करते हैं इसलिए उस मीडिया के अफवाह को आप लोग संशोधित करते हुए जो मेन विकास हो रहा है उस पथ पर हमको आगे बढ़ना है महोदय। महोदय,इसी के साथ आपने जो मुझको बोलने का समय दिया और सभी लोगों ने हल्ला करते हुए भी शोरगुल करते हुए भी मेरी बातों को सुना उसके लिए सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिन्द जय भारत।

(व्यवधान जारी)

श्री अमीत कुमार : सभापति महोदय हमारे नीतीश जी के सरकार के नेतृत्व में हमेशा देखा गया कि कहीं भी ग्रामीण विकास के लिए लोग आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं । हमारे क्षेत्र में हमेशा देखा गया है कि आज इन्दिरा आवास जिन लोगों को जरूरत है उनके बीच पहुंच रहा है लेकिन केन्द्र सरकार की अनदेखी के कारण पिछले दो वर्षों में इन्दिरा आवास की संख्या घटी है। मनरेगा को दखिये, मनरेगा में

भी विगत दो साल में हमारे बीच में जो भी लोग काम किये उनको भुगतान नहीं मिला है जिसके कारण वो अपने घर को छोड़कर बिहार के बाहर काम करने जा रहे हैं। इस पर ध्यान देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वह बिहार के साथ अनदेखी कर रही है इसको आपलोगों को देखना होगा। आप सिर्फ हमारे बातों को रोकने का काम करते हैं (व्यवधान जारी) क्योंकि बिहार की जनता अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, आपको भी उनके लिए लड़ना होगा चूंकि आपको इसीलिए यहां बैठायी है। (व्यवधान जारी)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आधा अधूरा सड़क बना हुआ है लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आपलोग यहां आकर के जनता को बरगलाने का काम करते हैं(व्यवधान जारी)हरदम हंगामा करते हैं।

(व्यवधान जारी)

टर्न-11/मधुप/15.3.16

श्री अमीत कुमार : ....क्रमश:... हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में जो भी जीविका चल रही है, उसमें देखिये कि कितने ढ़ंग से चलाया जा रहा है लेकिन बैंक जिसका नेतृत्व सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर में है, बैंक उसको अनदेखा करती है, उनका एकाउंट नहीं खुलता है, उनको लोन देने में बाधा करती है । आपलोगों को ध्यान देना पड़ेगा, आप उनकी बात जाकर दिल्ली में अपनी सरकार को बताइये कि हमारे बिहार की जनता के साथ क्या आप करना चाहते हैं, कैसे न्याय करेंगे । लेकिन आपलोग सदन के बीच में आकर हमेशा हमलोगों को डिस्टर्ब करते हैं और काम करने में बाधा पहुँचाते हैं ।

(व्यवधान)

आपको देखना पड़ेगा कि हमारे सीतामढ़ी में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, केन्द्र से हमारे सीतामढ़ी जिला को आप दिलायें जिससे कि सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चले । इसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा । आपकी सरकार वहाँ है, आपको जाकर बात करके बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की बात करें, देखना है कि आप क्या बिहार को दिला सकते हैं । हमारी यू0पी0ए0 की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में 5-5 ट्रेन सीतामढ़ी जिला को दिया गया था लेकिन आज क्या हुआ ? पिछले साल हम देखे कि एक भी ट्रेन सीतामढ़ी को नहीं मिला । आपको मंथन करना पड़ेगा और आपको जाकर बात करना पड़ेगा

बिहार की जनता का क्या हक है और हक की लड़ाई लड़नी होगी । आपको सोचना पड़ेगा । इस तरह से सिर्फ लोगों को बरगलाने से काम नहीं चलेगा । पानी आप दूसरे के लिए माँग रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपको अब प्यास लगा है तो आपलोग स्थिर हो रहे हैं और लग रहा है कि बाहर धीरे-धीरे निकल रहे हैं । आपको मंथन करना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

आज नीतीश जी की सरकार में पंचायतों में इंदिरा आवास योजना को अच्छे ढंग से चलाने के लिए 15 पंचायत पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, ब्लॉक लेवेल पर एक लेखा सहायक नियुक्त किया गया है । उनकी सोच है कि हर गरीब झोपड़ी में न मरे, एक पक्का मकान में मरने का काम करे और अपने परिवार के लोगों को कैसे आगे बढ़ाये, उसके लिए काम करे । लेकिन भा0ज0पा0 की सरकार यह नहीं चाहती है । पिछले दो साल में बिहार के लोगों के साथ जो केन्द्र की सरकार द्वारा नाइंसाफी की गई है, जो गलती किये हैं, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि बिहार की जनता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले दो साल में नरेगा में जो भी काम किये हैं, मजदूर को अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा है । इस गलती को कैसे आप सुधारियेगा, उसको बताना पड़ेगा । सिर्फ आप यहाँ आते हैं, लोग समझता है, ठग कर आप उसके लिये आये हैं लेकिन सवा लाख, पचास लाख, वह पैसा कहाँ गया, उसके बारे में भी जनता को आपको बताना पड़ेगा । बिहार में लोगों की समस्या को कैसे यहाँ रखना है, कैसे काम कराना है, रेल की कैसे व्यवस्था होगी, वह आप जाकर बात करें और आप हमारी जनता के लिए माँग करके लायें ।

हमारे नीतीश जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में हमने देखा है कि जीविका संस्था चल रही है जिसमें लोगों को एकजुट बनाकर महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे कि छोटे-छोटे लघु उद्योग का काम चल रहा है लेकिन उसमें भी कहीं-कहीं बैंक रोड़ा अँटकाने का काम कर रहा है ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य आप बोलिये ।

श्री अमीत कुमार : महोदय, मुख्यमंत्री जी की कुछ ऐसी योजनाएँ हैं जिसमें हमलोग देख रहे हैं, हमलोगों को देखना है और बात करना है कि समस्या क्या-क्या है । हमारे जिला में बहुत अपनढ़ लोग हैं, उनको बताना है कि उनके लिए क्या हमलोग कर सकते हैं । हमलोग नीतीश जी से रिक्वेस्ट करेंगे और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते

हैं कि आप जाइये, अपनी बात दिल्ली में रखिये कि आपकी जनता जिसके भरोसे आप यहॉ आये हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं ।

मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना है, जिसमें हमलोग देखे हैं कि कुछ लोग जिन्हें इंदिरा आवास मिला है, 10-20 हजार में काम पूरा नहीं कर पाये, उसके लिए हमलोग चाहते हैं कि उसमें संशोधन लाया जाय जिससे कि फिर से उनको योजना का लाभ मिल सके ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सरकार ग्रहण कर रही है, आप बोलिये ।

श्री अमीत कुमार : महोदय, नीतीश जी के नेतृत्व में गॉव-गॉव में हमलोगों ने देखा है कि हर जगह नाला बन गया है और सड़क को एक-दूसरे से जोड़ा जा रहा है । आज बच्चियों या बच्चे लोगों को स्कूल जाने में विदिन ए सेकंड अपने गॉव से हर जगह स्कूल पहुँच जा रहे हैं । अभी नीतीश जी की सरकार के नेतृत्व में गरीब के बच्चे भी आज कुछ बोल सकते हैं और पढ़ने का काम कर रहे हैं । आपको मंथन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि जिनके कारण आपको यहॉ भेजा गया है, उनके साथ आप धोखा कर रहे हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं । आप जरा सोचिए कि जिन लोगों ने आपको यहॉ भेजा है, जिनके बारे में आपको काम करना है, उनके घर तक जाइये, उनके दुख-दर्द को देखिये तब बात कीजिये । यहॉ आकर टी0वी0 में चमकने के लिए, मीडिया में छाने के लिए डेली आप जाकर बाहर में खड़ा होते हैं, कभी वेल में आकर खड़ा होते हैं । ऐसे चमकने से जनता का काम होने नहीं जा रहा है । आपको उनके लिए लड़ाई लड़ना होगा, अपनी बात यदि आप रखियेगा सदन के बीच में, तब लगेगा कि आप उनके बारे में सोचते हैं लेकिन आप हमेशा चाहते हैं कि लोग हमको टी0वी0 में देखे और मीडिया का कवर लेना चाहते हैं । ऐसे जनता बरगलाने वाली नहीं है । इसीलिये आपकी संख्या पिछले बार से कहॉ से कहॉ तक पहुँच गई है, आपको मंथन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आपलोग सरवाइव करेंगे । आप जनता का बहाना लेकर, कभी कुछ बहाना करके, कभी अपने लिए बोलियेगा, कभी चापाकल का बहाना लेकर सदन को डिस्टर्ब करते हैं....

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सही बोल रहे हैं, बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री अमीत कुमार : आज हमलोगों को बताना होगा, जनता को जवाब देना होगा, कब तक आप ऐसे कीजियेगा, कैसे सुचारू रूप से सदन चलेगा, इसके बारे में भी हमलोगों को जानना है । जनता की समस्या को लेकर हमलोग अपनी बात यहॉ रखते हैं और उनको बताना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है । प्रश्नकाल में भी सब लोग आते

हैं लेकिन जनता की बात को आपलोग रखने नहीं देते हैं, आपलोगों को जनता की बात को रखने का मौका देना होगा । कैसे जनता के बीच में हमलोग रहेंगे, कैसे उनकी बात को रखना है, उसके बारे में आपको सोचना होगा । आपको मंथन करना पड़ेगा । मीडिया में चमकने से कुछ होने नहीं जा रहा है । हल्ला करने से कुछ नहीं होगा ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : बोलिये-बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री अमीत कुमार : बहुत सारी समस्याएँ हैं । आपको नहीं सुनाई दे रहा है, आपको सुनना पड़ेगा । कितना दिन आपलोग जनता की बातों को अनसुना करियेगा । आपको सुनने के लिए मजबूर कर देंगे । जनता की समस्या पर कैसे काम करना है, उसपर आपको सोचना पड़ेगा और उसके बारे में मंथन करना पड़ेगा । टी0वी0 मीडिया में चमकने का काम छोड़कर जनता ने जिस काम के लिये आपको जीताया है, उसके बारे में सोचिये और कैसे काम कीजियेगा, यह बात कहिये । जनता की समस्या को लेकर आपलोग आइये और हम सब मिल बैठकर काम करेंगे । जनता का कैसे काम होगा, उसके बारे में हमलोग विचार करेंगे । लेकिन हमलोगों को नहीं लगता है कि जनता का काम आपलोग करना चाहते हैं, आपलोग हमेशा मीडिया और टी0वी0 पर रहने का काम करते हैं । जनता होशियार है, जनता आज के डेट में पीछे नहीं है, जनता समझ रही है इसलिये आपकी संख्या कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, उसपर भी सोचिये । कहाँ 100 था तो अब 53 पर आ गये हैं । आपको मंथन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब आप बैठ जाइये । राष्ट्रीय जनता दल- श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ।

(व्यवधान)

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : सभापति महोदय, जनहित से जुड़े अहम विभाग पर बोलने के लिए जो हमको अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गाँव में बसती है और देश का विकास गाँव के रास्ते ही सम्भव हो सकता है क्योंकि देश की 80 प्रतिशत आबादी गाँव में निवास करती है । इसी पर स्व0 चौधरी चरण सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर..... ...

क्रमशः...

टर्न–12/आजाद/15.03.2016

(व्यवधान)

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : (क्रमशः) डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है । मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने मेरा गाँव और मेरा देश का जो निश्चय किया कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा । लेकिन ये भाजपा वाले गांव की बात छोड़कर के स्मार्ट सिटी की बात करते हैं । उनको गांव के गरीबों से क्या मतलब, गांव के गरीबों के बारे में इनके सुशील मोदी कहते हैं कि हमारे लोग तो शहरों में बसते हैं, हमारे लोग तो गांवों में नहीं बसते हैं और यहां पर हंगामा करते हैं । आज जनहित का अहम मुद्दा था, जिसमें इंदिरा आवास, आदर्श ग्राम योजना, स्वयं सहायता समूह योजना इन तमाम बातों पर चर्चा होने वाली थी । सभापति महोदय, ये भाजपा वाले ने एक साल पहले आदर्श ग्राम योजना का एलान किया था लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसी आदर्श ग्राम योजना में फूटी कौड़ी पैसा देने का काम नहीं किया। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि इंदिरा आवास योजना बिहार में यू0पी0ए0 की सरकार में 6 लाख का चयन किया गया था, प्रतिवर्ष बिहार को 6 लाख इंदिरा आवास मिलता था । जब से एन0डी0ए0 की सरकार बनी है, 2,75,000 इंदिरा आवास की कटौती कर दी गई है और बिहार को मात्र 3,25,000 इंदिरा आवास दिया गया है । इन लोगों को शर्म नहीं आता है और ये लोग केन्द्र सरकार की बात करते हैं । मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह चलाकर के महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाया गया । महिलाओं के उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूह चलाया गया और इससे महिलाओं को रोजगार बढ़ा और महिलाओं में सशक्तिकरण हुआ । मैं भाजपा वाले से पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव का समय आता है तो इनको काला धन याद आता है और 15 लाख रू0 ये देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आयेंगे और देश का विकास होगा लेकिन जब भाजपा की सरकार बन गई तो इनके ही एक सांसद ने कहा था कि हर हिन्दू को चार बच्चे पैदा करना चाहिए । इन्होंने महिलाओं का अपमान भी करना शुरू किया । जनता के विकास का काम इनके समय में आज कहां होने वाला है ।

सभापति महोदय, हमारे बिहार में रोजगार गारंटी योजना चली, मजदूरों को काम मिला । जब से इनकी सरकार आयी, मजदूरों का काम रूक गया ।

मनरेगा का पैसा इन्होंने रोक दिया, रोजगार गारन्टी का पैसा इन्होंने रोक दिया, जिसके कारण मजदूर आज बेरोजगार हो गये । सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस भाजपा की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के रोजगार गारन्टी का 19,144 लाख रू0 बिहार का बाकी था, इसी तरह वित्तीय वर्ष 2014-15 का 18,983 लाख रू0 बकाया रखा । मुजफ्फरपुर जिला का वित्तीय वर्ष 2013-14 का 23 करोड़ 39 लाख रू0 बकाया रखा, 2014-15 का 14 करोड़ 65 लाख रू0 केन्द्र सरकार बिहार का पैसा बकाया रखा है । ये करोड़ों रू0 बिहार का रोजगार गारन्टी योजना का रखे और ये गरीब की बात करते हैं । सभापति महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मजदूरों के लिए रोजगार गारन्टी योजना चालू किया गया, उसी तरह से हमारे देश और हमारे राज्य के किसानों के लिए मजदूर गारन्टी योजना का प्रस्ताव यहां से भेजा जाय और उस प्रस्ताव में यह रहे कि जो मजदूर किसानों के खेत में काम करेंगे, उनका पैसा केन्द्र सरकार देगी और किसान अपने देख-रेख में मजदूरों से काम करायेंगे।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना का 5 हजार करोड़ रू0 केन्द्र सरकार के यहां बकाया है और केन्द्र सरकार बिहार सरकार को पैसा नहीं दे रही है ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : भगवान आपलोगों को बुद्धि दे ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : सभापति महोदय, आपने एक शेर कहा था -

अंधा चकाचौंध का मारा,
क्या जाने इतिहास बेचारा ।

ये भाजपा वाले ने मजदूरों का पैसा रोक लिया और ये आज हल्ला कर रहे हैं । सचमुच मैं कहता हूँ कि इंदिरा आवास में कटौती किसका हुआ, मजदूरों का मनरेगा में पैसा किसने रोका तो इसपर बोलने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं । ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए यहां पर ढ़ोल बजाते हैं और इनका काम यही पर तमाम हो जाता है ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, गांवों का चहुमुखी विकास शुरू हुआ है और बी0जे0पी0 के लोग उसमें अवरूद्ध पैदा करती है । मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीब विरोधी रही है । गांवों के विकास से इनको कोई मतलब नहीं रहा है । जब चुनाव आता है तो लोगों को ये तरह-तरह के सपने दिखाते हैं और आज भी सपना दिखाने के लिए चापाकल के बारे में कह रहे हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर

घर में नल की व्यवस्था कर रहे हैं और स्वच्छ जल की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। सरकार ने नल से पानी देने की योजना बनायी है और ये चापाकल से पानी पीने की बात कहते हैं । मैं आसन के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि बार-बार ये सदन में या सदन से बाहर कहते हैं कि बिहार में जंगल राज-2 आ गया । मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के साथी से कि जिस समय गोधरा कांड हुआ था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने नरेन्द्र मोदी के बारे में कहा था कि उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया । अमित शाह को गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात में घुसने पर रोक लगा दिया था । ये कहते हैं गुजरात का विकास मोडल और बिहार में जंगल राज । मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 1990 से पहले यही वह सदन है, जिसमें 1990 से पहले कौन-कौन लोग जीत कर आते थे और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है कि गरीब-गुरबा का बेटा और बेटी भी आज सदन में मौजूद होता है । यह हमारे राष्ट्रीय जनता दल का ही देन है । सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिनको जनता से कोई मतलब नहीं रहा है, इन्होंने हमेशा बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया है, बिहार में विकास को कैसे रोका जाय, इसपर इन्होंने ध्यान दिया है । अब जब बिहार का विकास नहीं रूक रहा है तो ये लोग सदन में हल्ला कर रहे हैं । बिहार का बंटवारा भी किसने किया था, जब केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी । इसलिए बिहार को बांटने वाला काम भी यही बी0जे0पी0 वाले लोगों ने किया था । अब बिहार की तमाम भूसम्पदा आज झारखण्ड में चली गयी । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि अपने सीमित संसाधन के बावजूद बिहार बंटवारा के बाद मुझे बालू और पानी मिला, उसपर जब महागठबंधन की सरकार विकास के रास्ते पर चल रही है तो उनको खटक रहा है। बालू को भी रोकने का काम ये भाजपा वाले ने किया है, अभी तक प्रमिशन नहीं दिया है, जिससे करोड़ों मजदूर लोग बेरोजगार हो गये हैं । मैं कहना चाहूँगा कि लालू जी के बारे में ये सिर्फ बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि लालू जी वह सख्सियत है, जिसने डॉ0 राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और महात्मा गॉधी जैसे लोगों के विचार को जिन्दा रखा और उनके विचार को पूरा करने का काम किया । इसी पर एक कहावत याद आती है - हजारों वर्ष नरगीस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर चमन में एक दिदावर पैदा होता है, उसी तरह लालू यादव दिदावर जैसा पैदा हुआ है । ये लोग जितना चिल्लायेंगे जंगल राज, गांव के गरीब लोग जानते हैं । ये बी0जे0पी0 वाले गरीबों की सरकार को जंगल राज कहते हैं, हमलोग उतना ही मजबूत होते हैं । ये जितना जंगल राज कहते हैं, गरीब लोग लालू यादव जिन्दाबाद

करते हैं । मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अभी-अभी एक घटना घटी है - मुजफ्फरपुर जिला में ''मैं जे0एन0यू0 बोल रहा हूँ'' उसपर संवाद होने वाला था, वहां के नगर विकास आयुक्त ने प्रमिशन दिया और जे0एन0यू0 के प्रोफेसर और स्टुडेन्ट आये थे मुजफ्फरपुर में लेकिन नगर विकास आयुक्त इन भाजपा वाले लोगों का शिकार होकर के जिस दिन उनका संवाद था, उस संवाद को रद्द कर दिया । इसका नतीजा हुआ कि मुजफ्फरपुर जिला में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया । माननीय सभापति महोदय से आग्रह करूँगा और कहूँगा कि बिहार की जनता ने तो इनको सबक सिखा दिया, बिहार की जनता ने भाजपाईयों को सबक सिखा दिया लेकिन सिस्टम में अभी भी भाजपाई जिन्दा है और रह रहे हैं । इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सिस्टम में जो बैठे हुए भाजपाई हैं, उनको भी सिस्टम से हटाया जाय ताकि जनता का काम हो सके । बड़े-बड़े ओहदे पर जो गरीबों के रहनुमा कह करके बैठे हुए हैं, वे गरीबों का काम नहीं होने देते हैं । विकास के काम में बाधा डालते हैं । माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने पिछले दिनों कहा था कि जिस विभाग में काम नहीं होगा, उस विभाग का पैसा कटौती कर देंगे । मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि विकास का पैसा अगर आप कम कर देंगे तो यह जनता के हित में नहीं होगा । जिस विभाग का पैसा कम खर्चा हो, उस विभाग के पदाधिकारी पर कार्रवाई किया जाय, उसको निलंबित किया जाय क्योंकि विभाग का पैसा क्यों नहीं खर्चा हुआ ?

..... क्रमशः .....

टर्न-13/अंजनी/दि0 15.03.16

....क्रमशः.....

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि भाजपा वाले कहते थे कि हम काला धन वापस लायेंगे और हर खाते में 15-15 लाख रूपया भेजेंगे, साल में दो करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, नौकरी क्या देंगे, नौकरी ही बंद कर दिया, 15 लाख रूपया के बदले 15 रूपया खोटी कौड़ी नहीं दिया, अच्छे दिन आयेंगे, अच्छा दिन क्या आयेगा, उससे भी बुरा दिन ला दिया । देश का एक सबसे बड़ा इन्स्टीच्यूट है जे0एन0यू0, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसमें के छात्र विश्व हिन्दू परिषद के खिलाफ, आर0एस0एस0 के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो उस आदमी को वह देशद्रोही कहता है । ये पूरे देश में केवल भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि कोई

उसके खिलाफ नहीं बोले, आर0एस0एस0 के खिलाफ न बोले, जो संभव नहीं है । मैं आपको चुनौती देता हूँ कि पहले आपकी संख्या क्या थी और आज आप कहां है, अभी आप वेल में खड़े हैं । आपको जनता देख रही है, आने वाले समय में आपको रोड पर खड़ा करेगा, आप संसद को देखने लायक नहीं रहियेगा, यह आपको बिहार की जनता बतायेगी । गुमान आप मत कीजिए, आने-वाला 2019 में लोक सभा का चुनाव होने वाला है, बिहार की जनता यह महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल ठगने वाली पार्टी है । राम विलास भाई को ये लोग कहते हैं, एक कहावत है हुजूर- एक तो करेला और दूसरे चढ़ गये नीम के पेड़ पर । श्री राम विलास जी तो पहले से ही करेला हैं और दूसरे चढ़ गये बी0जे0पी0 जैसे नीम के पेड़ पर, तो आनेवाला जो चुनाव होगा 2019 में, उस समय इनको भी पता चल जायेगा कि हम मौसम वैज्ञानिक हैं कि क्या हैं ? इनको पता नहीं है, बिहार का मौसम वैज्ञानिक, बिहार का डॉक्टर माननीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी हैं और दूसरा कोई पैदा नहीं लिया है और न पैदा लेगा ।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिला का मीनापुर विधानसभा क्षेत्र है । मुजफ्फरपुर जिला का यह सबसे बड़ा सब्जी उत्पादन का केन्द्र है और वहां से पूरे देश के महानगरों में सब्जी सप्लाई होता है । हुजूर, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो औने-पौने भाव में सब्जी बेच देते हैं चूंकि वहां पर भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारे मीनापुर में सब्जी के भंडारण एवं रख-रखाव की व्यवस्था की जाय । दूसरा, हमारे यहां प्रखंड मुख्यालय है जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, सारे पदाधिकारी शहर में डेरा डालकर रहते हैं, कोई आदमी प्रखंड में नहीं रहता है, जिससे आम लोगों को काम में काफी कठिनाई होती है, तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि यथाशीघ्र वहां भवन का निर्माण किया जाय ताकि प्रखंड एवं अंचल में सारे पदाधिकारी मुख्यालय में रह सकें । तीसरा, यह कि वर्ष 2007 की एक बात याद आ गयी हुजूर, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वर्ष 2007 के बाढ़ में हमारे क्षेत्र में गये थे, उस समय मैं इस सदन का सदस्य नहीं था लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री वहीं हैं और मैं सदन का सदस्य हूँ । वर्ष 2007 में उन्होंने कहा था कि मीनापुर के हरसेर घाट में गंडक नदी पर और चांदपुरवा में, दोनों जगह पुल का निर्माण किया जायेगा । मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वहां हरसेर घाट पर और चांदपुरवा में अगर पुल बन जाता है तो हमारे गांव के लोगों को, जो फोर लेन बनाने में दस हजार करोड़ रूपया एक किलोमीटर

रोड में लगा है और गांव से निकलने के लिए लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, वहां पर पुल बन जाने से लोगों को 20 किलोमीटर प्रखंड मुख्यालय आने में दूरी कमेगी और चार किलोमीटर फोर लेन पर जाने में लगेगा । इसलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वहां पर पुल का निर्माण कराया जाय ताकि मीनापुर का विकास हो । चौथा, यह कि हमारे यहां छोटी-छोटी पुल-पुलिया है, एक तरफ जुरन छपरा, कई बाद इसका टेंडर हो गया लेकिन कोई टेंडर नहीं लिया, रिवीजन के लिए वहां से स्वीकृति लेने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग पटना में आया हुआ है, मैं आग्रह करूँगा कि इसका यथाशीघ्र टेंडर कराया जाय ताकि क्षेत्र को आने-जाने में सहुलियत हो । तमाम् बातों को रखते हुए मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : भाकपा माले नेता जनाब महबूब आलम से दरख्वास्त करता हूँ । महबूब आलम, आप बोलिए।

श्री महबूब आलम : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या-42 पर बोलने के लिए आपने जो मौका दिया, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ । महोदय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गयी है लेकिन हम बार-बार यह बात बोल रहे हैं कि हजारों-लाखों की संख्या में अभी-भी गांव में गरीब हैं, जिनका बी0पी0एल0 में नाम नहीं है और बी0पी0एल0 से वंचित गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है । हम मानते हैं कि ग्रमीण विकास अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । कृषि मजदूर और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, प्रतिवेदन में कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी 189 रूपया देते हैं और ये अपनी पीठ थप-थपा रहे हैं कि 30 दिन का 189 रूपया जोड़ दिया जाय तो 5670 रूपया होता है और आसमान छूती महंगाई में 5670 रूपया से क्या हो सकता है महोदय । यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं महोदय । महोदय, हम बात करते हैं कि किन्हीं वजह से ग्रामीण जनता, ग्रामीण नौजवान, गांवों से हजारों-लाखों की संख्या में मजदूर पलायन कर गये हैं । मजदूर पंजाब, बंबई, हैदराबाद जैसी जगहों में जाते हैं और पंजाब जैसी जगहों में ट्रक और टेम्पो चलाकर जीवन को खतरा में डालते हैं और मार खाने के लिए मजबूर होते हैं । महोदय, इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण विकास विभाग में किसी तरह की गारंटी नहीं की गयी है । महोदय, हम मांग करते हैं कि आज कृषि व्यवस्था जो संकट में है, किसान को सरकार उचित मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी नहीं दे पाती है, उसके लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ा

जाय और किसान से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था ग्रामीण मजदूरों की, कृषि मजदूरों की, खेत मजदूर के साथ-साथ अन्य ग्रामीण जो मजदूर हैं, उनका 500 रूपया न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाय । महोदय, हम मांग करते हैं कि आज भी काम का अभाव है, गांव या ग्रामीण क्षेत्र में मशीन आधुनिकीकरण होने की वजह से काम का अभाव हो गया है, इसलिए मनरेगा के साथ कृषि को जोड़ा जाय और 200 दिन का कार्य दिवस स्थापित किया जाय । आज भी कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था के लिए प्रतिवेदन में कोई बात नहीं की गयी है, बड़ी-बड़ी डींग हांकते हैं ये लोग और इन लोगों को पता नहीं है कि गांव की हालत क्या है ? महोदय, गांव में जो ये सड़क बनाते हैं, वह सड़क जिनकी क्षमता 20 टन है, उन सड़कों में ओवरलोडेड ट्रक 60 टन-65 टन-70 टन की गाड़ी जाकर एक महीना के अन्दर सड़कों को बर्बाद कर देती है और इनके अफसर घूस लेकर इन ओवरलोडेड गाड़ियों को निर्वाध रूप से उन सड़कों में चलने देते हैं । महोदय, मैं इन लोगों को चुनौती देता हूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर ये बात करते हैं, ग्रामीण विकास की अगर बात करते हैं, जमीन पर तो होता नहीं होगा । आज महोदय, इन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पानी....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : एक मिनट सदस्य ।

श्री महबूब आलम : पीने का पानी, एक भी चापाकल नहीं है, चापाकल की व्यवस्था की जाय । न तो नौ मन घी होगा और न राधा नाचेगी । महोदय, ये जो गांव-गांव में पाईप लेकर पानी देने की व्यवस्था करते हैं तो 1972 से जल मीनार बना हुआ है, उन जल मीनारों की क्या हालत है, इसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए । महोदय, जहां दस साल पहले हमारे बलरामपुर में एक जल मीनार बना हुआ था, उससे एक बूंद पानी उन गांव के लोगों को नहीं मिली है । महोदय, विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो केन्द्रीय योजनाओं में मनरेगा में कटौती की गयी है, इनसे हमलोग मांग करते हैं मनरेगा में कटौती क्यों हुई, आपको सवाल उठाना होगा, आपको जवाब देना होगा, सिर्फ नरेन्द्र मोदी कहकर इस जवाब से बच नहीं सकते हैं ।

टर्न–14/शंभु/15.03.16

श्री महबूब आलम : क्रमशः.....महोदय, सिंचाई के लिए हमारे सीमांचल में कोई व्यवस्था नहीं है। महोदय, हमने कहा है अपने बजट भाषण में कि हमारा बलरामपुर क्षेत्र नदी नालों से घिरा हुआ है, बहुत सी जो प्राकृतिक धाराएं हैं उन धाराओं को विकसित किया जाय, मनरेगा से जोड़ा जाय तो एक नाम का रूप ले सकता है और कृषि विकास और ग्रामीण विकास का एक नया रूप हो सकता है। महोदय.....

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : महबूब आलम जी, भाषण जारी रखिये।

श्री महबूब आलम : महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी गरीबों के पास आवास, बास की जमीन नहीं है। ये वादा करते हैं कि 5 डि0 जमीन हम देंगे, लेकिन इससे पहले ब्रिटिश जमाने में 1948 में बिहार प्रिवलेज परसन होम स्ट्रीट लैंड के तहत एक कानून बना हुआ था जो कानून स्ट्रीट एक्ट अभी भी अस्तित्व में है। 12 डि0 जमीन होम स्ट्रीट लैंड के तहत पर्चा दिया जायेगा, लेकिन आज तक जिन लोगों को जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जिंदगी बर्बाद करते हैं। आज उनके लिए किसी किस्म की योजना की बात नहीं है। महोदय, खेतिहर मजदूर जो सारी जिंदगी कुपोषण से 55 साल के पहले भी बूढ़ा हो जाते हैं। महोदय, मैं इस सदन से मांग करता हूं कि ग्रामीण मजदूरों को वृद्धावस्था पेंशन दिया जाय और 55 साल उसकी आखरी उम्र रखी जाय। 55 साल के बाद वे काम के लायक नहीं रहते हैं।

सभापति (श्री इलियास हुसैन) : अच्छी बात है, सरकार विचार कर रही है।

श्री महबूब आलम : और इन लोगों से भी हम मांग करते हैं कि आपलोग भी अपनी योजना में इन बातों को लाइये, सिर्फ यहां चिल्लाने से चीखने से नहीं होगा। सांप्रदायिक फासीवाद की जो बात है आप दूसरे को बोलने नहीं देते हैं, समाज में एक्सप्रेशन पर जो हमला करते हैं, आपका जो फासीवादी चेहरा बेनकाब हो रहा है, यहां भी बेनकाब हो रहा है। महोदय, उसपर भी इनलोगों को चिंतन करने की जरूरत है।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : आ हा हा.....क्या वक्तव्य है, बहुत शानदार वक्तव्य है आपका।

श्री महबूब आलम : मैं इन तमाम बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : मैं तो चाहता था कि आज महबूब आलम साहब आज अपनी इच्छा पूरी कर लें। अब जनता दल युनाइटेड जनाब हेम नारायण साह जी।

श्री हेम नारायण साह : सभापति जी, आज हम ग्रामीण विकास विभाग के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। हम सदन के सभापति महोदय, माननीय मंत्रीगण,

माननीय सदस्यगण का स्वागत करते हैं, अभिनन्दन करते हैं कि हम सदन में पहली बार आये हैं और पहली बार बोलने का मौका दिया गया है।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : नीतीश जी पानी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पानी दे रहे हैं। अच्छा भाषण दीजिए और विस्तार से।

श्री हेम नारायण साह : इसलिए हम महोदय का आभार प्रकट करते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है।

सभापति(श्री इलियास हुसैन) : बिना पानी के आपलोग खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री आपको पानी पिला रहे हैं और अंतिम दौर तक पिलायेंगे।

श्री हेम नारायण साह : हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को मॉडल बनाने की सोच रहे हैं विरोधियों को सोचना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं एक तरफ विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है- जैसे कि हर योजना में केन्द्र सरकार कटौती करती जा रही है ताकि हमारा बिहार आगे न बढ़े। हम विरोधियों से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सात निश्चय है- ये लोग घबड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अगर सात निश्चय धरातल पर आ गया तो हम 2019 में, 2020 में गांव-गांव में किस तरह से वोट मांगने जायेंगे, हम किस हक से कहेंगे कि हमें विकास करना है हमें वोट दीजिए। इसकी चिंता विरोधियों को है। विरोधी यह नहीं देख रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सड़क योजना से जो सड़क बना हुआ है, हमारे ग्रामीणों को आनेजाने में सुविधा हो रही है। ग्रामीण जो पैदा करते हैं चावल, दाल, धान सब ले जाने में सुविधा हो रही है। हम यह कहना चाहते हैं कि जो सात निश्चय है हर घर को नल का जल, हर घर को शौचालय, हर बेरोजगार युवक, युवतियों को 1-1 हजार दो साल तक बेकारी भत्ता और कॉलेजों में वाई फाई की सुविधा यह सब विरोधियों को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सुविधा अगर धरातल पर आ गया तो केन्द्र सरकार क्या करेगी। हम इन लोगों से कहना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार जो योजनाओं में कटौती कर रही है, आप कटौती बंद करें और बिहार को एक नया बिहार बनाने के लिए प्रयास करे। हम इन लोगों से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बिहार एक नंबर होगा और मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। यह निश्चय लिये हैं और ये लोग शहर को स्मार्ट बनाने की सोच रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री गांव को स्मार्ट बनाने के लिए सोच रहे हैं। इन लोगों से यह कहेंगे कि आप गांव को देखिए, गांवों में विकास हो रहा है, आपको भी दिखायी दे रहा है। आप जब शाम को निकलते हैं गांव में तो देखते हैं कि चकाचक बिजली सब तरफ दिखायी देती है, पता नहीं चलता है कि यह गांव है कि शहर है। इनलोगों को

देखना चाहिए कि केन्द्र सरकार कटौती न करे, बिहार को आगे बढ़ाने में मदद करे। हम विरोधी लोगों से कहना चहाते हैं कि आपलोग देखिए बिहार में विकास हो रहा है। हमारे किसान भाइयों को खेती करने के लिए उत्तम बीज मिल रहे हैं, उत्तम क्वालिटी के खाद मिल रहे हैं। हमारे किसान भाई ऐसी खेती करते हैं कि उसका जीता जागता प्रमाण है कि आपको हमको सबको सालो भर हरी सब्जियां दे रहे हैं हमारे किसान भाई। यह आप देखिए कि हमारा बिहार विकास कर रहा है। आप देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं क्योंकि विकास की एक जड़ है शिक्षा तो शिक्षा कैसे आगे आवे। बजट में 24 परसेंट रूपया शिक्षा पर मुख्यमंत्री खर्च करने जा रहे हैं। आप विरोधी लोगों को देखना चाहिए कि बिहार विकास करे न कि बिहार को गर्त में ले जाने की आप सोच रहे हैं। दो साल पहले माननीय प्रधानमंत्री आते थे और जुमलाबाजी करके चले जाते थे कि हम 15 लाख रूपया एक-एक खाते पर देंगे, क्या हुआ तेरा वादा, कहां गया तेरा वादा ? आज फिर जुमलेबाजी कर रहे हैं । बिहार की एक-एक जनता निगाह लगाकर बैठी थी कि भारत के प्रधानमंत्री बिहार आये हैं तो बिहार को कोई नया तोहफा देकर जायेंगे, लेकिन खाली हाथ आये और खाली हाथ चले गये, बिहार की जनता इंतजार करते रह गयी, कुछ नहीं मिला बिहार को तो हम आपलोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग बिहार को विकसित बनाने में केन्द्र से कहिये कि सौतेला व्यवहार न करे। जय हिन्द।

टर्न-15/अशोक/15.03.2016

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): राष्ट्रीय जनता दल, माननीय सदस्य डा. शमीम अहमद ।

श्री शमीम अहमद : सभापति महोदय, वर्ष 2016-17 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके पक्ष में और सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आज जिस तरह से इस देश में महौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी विपक्षी द्वारा, आज भी सदन में विपक्ष को देखा जा रहा है। महोदय, जिस तरह से इस देश में लालू जी, नीतीश कुमार जी, सोनिया जी ने मिलकर महागठबन्धन बना करके इस चुनाव को लड़ा और जिस तरह बिहार की जनता ने इन नेताओं को स्वीकार किया, वह काबिलेतारीफ है । बिहार की जनता को आपके माध्यम से, बिहार की जनता को लाख-लाख शुक्रिया अदा करता हूँ,

लाख-लाख बधाई देता हूॅ । महोदय, आज जिस तरह केन्द्र की सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, आज जो बजट चल रहा है, वह मेन ग्रामीणों के लिए चल रहा है, भाजपा के लोग इसको पचाने में नाकाम रहते है चूंकि ये सिर्फ शहर के विकासोन्मुख होते हैं, गांव के विकास की तरफ इनका ध्यान नही रहता है महोदय । मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा लिये गये सात निश्चय का मैं समर्थन करता हूॅ और आज से पहले गांव में जो भी विकास हुये हैं, बहुत सारे विकास हुये हैं, यू.पी.ए. -वन में माननीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे और यू.पी.ए. वन में ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश बाबू थे तो उस वक्त गांव के लिए स्पेशल योजना बनाकर के और गांव पर विशेष ध्यान देते हुये उन्होंने ग्रामीण कार्यो के लिए पैसा दिया था । जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नतीश कुमार जी की सरकार बनी उस समय से गांव पर ध्यान दिया गया और गांव के लिए बहुत सारी योजनायें चलाई जा रही है, जैसे पक्के नाले, सड़कें बने हैं, लेकिन महोदय आज भी इसमें कमी है । महोदय, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा योजना बनाये गये है, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूॅ कि क्या बिहार में इसके लायक एक भी शहर नहीं था जिसको आप स्मार्ट सिटी बनाते ? यह सिटी पहले से ही सज-धज के तैयार है तो प्रधानमंत्री इसके लिए क्या करेंगे ? महोदय, एक स्मार्ट सिटी के खर्च में सैकड़ों गांव विकसित हो जाते, आज भी इस बिहार में 80 से 90 प्रतिशत लोग देहात में रहते हैं । लेकिन केन्द्र के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । आज हमारे मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी ने सात निश्चय लिया है कि कैसे गांव का विकास हो । इन गांवों का विकास कैसे हो, इन गांवों में कैसे सड़कें बने जो बाकी पड़े हुये हैं, नाले बने- इसलिए उन्होंने सात निश्चय लाया हैै, जिसमें आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को आधार, घर-घर बिजली, घर-घर पानी- घर तक पक्के नाले, हर घर शैचालय, अवसर बढ़े आगे बढ़ें । आज हमारे विपक्षी भाइयों द्वारा पानी के लिए हाहाकार मचाये जा रहे हैं, हमारे सात निश्चय में हमारी सरकार इसको पहली प्राथमिकता देते हुये हर घर में नल देने का वायदा किया है ।

महोदय, आज जो बजट पेश हुआ है वह है पचपन अरब दस करोड़ छः लाख आठ हजार रूपये से अनधिक राशि का है, यह बिहार के गांव के लिए है । नरेगा में केन्द्र सरकार ने मजदूरी काट कर के जो सरकार मजदूरों की मजदूरी 177 रूपये दे रही थी उसको घटाकर के इस केन्द्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने 162 रूपया

कर दिया , इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है महोदय ? आज मजदूर का भी पैसा घटाया जा रहा है ।

आज गांवों के लिए जो इन्दिरा आवास की योजना है उसमें भी कटौती की गई है । मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि इन्दिरा आवास में और इस मनरेगा में भी जो कटौती की गई है उसको डबुल किया जाय और इसमें 100 दिन से बढ़कार 200 दिन का रोजगार दिया जाय । तब तक इस बिहार का और देश का विकास नहीं होगा जब तक हमारा देश गांव की तरफ से आगे नहीं बढ़ेगा । आज हमारे गांव में बहुत सी कमी है, नाला है, सड़क है, एडुकेशन है, सभी में हम पीछे हैं, सिर्फ भाजपा के लोगों को टाऊन पर ही ध्यान रहता है, स्मार्ट सिटी कि तरफ ही ध्यान जाती है । मैं फिर केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा धन देकर के गांव के दबे-कुचले लोगों को एक सूत्र में लाने पर बल दे ।

आज 15 साल के माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता रहा है, लेकिन भाजपा भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आज भी इस सदन में, आज जो हम यहां हैं वह लालू जी की देन है, आज दलित और महादलित के लोग यहां जीत कर आयें हैं चूंकि लालू जी ऐसा नेता थे जिन्होंने मानसिक आजादी दिलाई है महोदय और न्याय के साथ विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्व प्रसाद यादव जी इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं ... ..

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): आप अपना क्षेत्रीय मांग रखिये ।

(व्यवधान)

श्री शमीम अहमद : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप- मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री से यह मांग करता हूँ कि जो भी हमारे गांव हैं, जिस तरह से केन्द्र सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने का निश्चय लिया है - मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, उप- मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री से यह मांग करता हूँ कि एक प्रखण्ड में कम से कम दो पंचायत लिये जायं, जिन्हें स्मार्ट बनाया जाय और वहां पर हर तरह की सुविधा हो- एडुकेशन के लिए कई प्रकार के स्कूल हों महोदय, ग्राम कचहरी हों, जिसमें सरपंच बैठे, पंच बैठे और छोटे-छोटे मुद्दे को वहां पर खत्म करें क्योंकि हमारे ग्रामीण जनता अनपढ़ होते है। , पढ़-लिखें कम होते हैं, छोटी-छोटी बातों में झगड़ जाते हैं और उस झगड़ें में फंसे रह जाते हैं । वहां पर प्राईमरी एडुकेशन, सेकेन्ड्री एडुकेशन और हायर एडुकेशन हो महोदय ।

स्मार्ट पंचायत के लिए जो पंचायत चुने जायं उसमें बैंक हो और उसमें माइक्रो फाइनेन्स की व्यवस्था हो । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना

चाहता हूँ कि गांवों में पशुओं की संख्या कम होती जा रही है, मैं आपके माध्यम से अच्छे नस्ल के पशु को इस माइक्रों फाइनेन्स बैंक द्वारा मंगा कर के ग्रामीण जनता में बांटा जाय महोदय जिससे कि उनका जीवन व्यतीत हो सके । सभी को आवास मिले- इन्दिरा आवास योजना के अतिरिक्त एक योजना बनाई जाय जिसमें, जिसको आज तक छत नहीं है, पत्थर पड़ने लगते हैं, ऑधी आती है तो उन लोगों को कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है । हम भी गांव में रहते हैं महोदय । उन लोगों की परेशानी देखकर सरकार से आग्रह करूंगा, मंत्री जी से आग्रह करूंगा, इस मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार ने जो इन्दिरा आवास में कटौती की है उसको अपने स्तर से, जिनके पास गांव में आवास नहीं हैं, आप अपने स्तर से आवास बनाने का काम किया जाय ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): अब आप समाप्त करें ।

श्री शमीम अहमद : दो मिनट में मैं खत्म करता हूँ । हमारे नरकटिया विधान सभा क्षेत्र में महोदय, बनकटवा प्रखण्ड है महोदय, वनजरिया प्रखण्ड में साल में कम से कम दो-तीन बार बाढ़ आ जाती है, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि स्पेशल पैकेज बनजरिया प्रखण्ड के लिए दिया जाय ताकि वह मुख्य धारा से जुड़े । क्रमशः

टर्न-16-15-03-2016-ज्योति

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव ।

श्री अचमित ऋषिदेव : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । गांवों के विकास के बगैर किसी भी प्रदेश या देश का विकास सभव नहीं हो सकता है । राज्य सरकार ग्रामीण आबादी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रमों को चला रही है । जिसमें बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने पर जोर दिया गया है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य माईक पर बोलिये । माईक को सामने कीजिये।

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार गांवों के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है । राज्य सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति एवं अन्य वर्गों के गरीब लोगों को सम्मान के साथ विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अनेकानेक नयी योजनाओं की शुरुआत कर नयी पहल की गयी है । ग्रामीण

विकास विभाग इसमें अहम भूमिका निभाने का कार्य किया है । विभाग मजदूरी, नियोजन, स्व–रोजगार, गृह विहीन ग्रामीण गरीब लोगों को इन्दिरा आवास , ग्रामीण सड़क एवं आहर– पाईन के किनारे वृक्षारोपण सहित ग्रामीण सड़क निर्माण जैसी अनेक योजनाओं को चला रहा है।

जीविका के तहत वित्तीय सहायता देकर 4 लाख 60 हजार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण लोगों को अपना खुद का रोजगार खड़ा करने में मदद किया जा रहा है ।

तेंदुलकर समिति द्वारा किए गए अनुमान के आधार पर 2004 से 2012 के बीच बिहार में गरीबी अनुपात में लगभग 21 प्रतिशत अंको की कमी हुई है । बिहार में मनरेगा समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम बन गया है । वित्तीय वर्ष 2015–16 के दिसम्बर 2015 तक 3 करोड़ 52 लाख 69 हजार मानव दिवस सृजित किया गया है जिसमें 12 हजार परिवार को रोजगार दिया गया है । मनरेगा अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 177 रुपये दी जा रही है जो भारत सरकार के निर्धारित मजदूरी की दर से 15 रुपये अधिक है । जिसका वहन राज्य सरकार अपने खजाने से कर रही है ।

किसी गृह विहीन व्यक्ति के सिर के ऊपर छत उपलब्ध हो जाना उसके लिए अनिवार्य सम्पत्ति बन जाती है । यह उसके शारीरिक और मानसिक खैरियत में सुधार लाता है । वर्ष 2012–13 से इंदिरा आवास योजना के तहत शत प्रतिशत से भी अधिक भौतिक लक्ष्य हासिल हुए हैं जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हिससे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । जिनका आवास किसी कारण पूर्ण नहीं हो सका था उन्हें मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार द्वारा 30 हजार की दर से राशि का भुगतान कर 5 हजार 7 सौ 62 आवासों को पूर्ण किया गया है । जिससे कुल मकानों में उनका हिस्सा 90 प्रतिशत तक पहुंच चुका है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : पानी नीतीश कुमार जी नहीं देंगे तो कौन देगा , पानी आखिर मुख्यमंत्री ही न देंगे ? माननीय सदस्य ,ऋषिदेव अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव :एक मिनट में । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बसावटों के लिए सम्पर्क सड़क, उनका पककीकरण एवं नाली निर्माण की 6 हजार 8 सौ 22 योजनाएं पूर्ण की गई है और 66 हजार 7 सौ 97 योजनाओं में कार्य हो रहे हैं ।

पंचायतों में 4 सौ 18 मनरेगा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और 3 हजार 5 सौ 4 योजनाओं पर कार्य चल रहा है । राज्य में 6 करोड़ 22 लाख लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है । सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत 52 ग्राम पंचायतों का बेस लाईन सर्वेक्षण पूर्ण कर ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गई है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : मैं अब अपने निर्वाचन क्षेत्र रानीगंज में आमलोगों को जन सुविधा दिलाने केक लिए यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान में रानीगंज प्रखंड में कुल 32 पंचायत हैं जिसमें बसैटी के आसपास के 13-14 पंचायतों की दूरी रानीगंज से काफी अधिक है । इससे आमलोगों को सामान्य कार्य के लिए भी प्रखंड आने-जाने में काफी दूरी तय करना पड़ता है । अत- मैं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जन सुविधा को बढ़ाने के लिए रानीगंज के 13-14 पंचायतों को अलग कर बसैटी को एक नसया प्रखंड बनाने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य ऋषिदेव अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अंत में मैं गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नये पहल एवं प्रयासों को दिशा देने के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब मैं राष्ट्रीय जनता दल श्री राम विलास पासवान जी से आग्रह करता हूँ ।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के बजट का समर्थन करता हूँ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कड़े अंदाज में बोलिये ।

श्री राम विलास पासवान : मैं बजट का समर्थन करना चाहता हूँ और सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, आज बिहार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकास का काम किया जा रहा है, वह सराहनीय है । गरीब गुरबा इस विकास से लाभान्वित` हैं । महोदय, गली गली में सड़के बन रही हैं । मनरेगा

के तहत किसानों के लिए पोखर की खुदाई हो रही है । मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है । ग्रामीण विकास विभाग से जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसानों के हित मे मनरेगा द्वारा सराहनीयं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । मजदूरों को मजदूरी के लिए मनरेगा योजनाएं चलायी जा रही हैं वह भी सराहनीय है।ं महोदय, इन्दिरा आवास में केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार इस सरकार के साथ करने का काम किया है । केन्द्र सरकार से जो आंवटन आता है उसमें कटौती कर रही है । महोदय, जबकि केन्द्र में जब यू0पी0ए0 सरकार थी वह इसतरह से भेदभाव नहीं करती थी और इसतरह से इन योजनाओं में कटौती नहीं करती थी । यू0पी0ए0 सरकार में बिहार के 7 मंत्री थे और उनलोगों ने बिहार को बचाने का काम किया था । नरेन्द्र मोदी की सरकार झूठ बोलकर गद्दी पर बैठी । झूठ बोलकर गद्दी पर बैठने वाली केन्द्र सरकार बिहार के विकास के नाम पर ठगने वाली सरकार है । इसके लिए बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी ,माफ नहीं करेगी । नरेन्द्र मोदी जी बिहार के नागरिक अपनी दशा और दिशा तय कर चुके हैं और जो झूठ बोलने का काम किया गया है उसके लिए बिहार की जनता 2019 में आपको बख्सने नही जा रही ं है । 2019 में आपको गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा । यह निश्चित तय है महोदय, आज विपक्ष द्वारा पानी की मांग की जा रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब गुंरबा के लिए नल से पानी पहुंचाने का निर्णय किया है । चापाकल पुरानी सोच है जबकि नल द्वारा पानी देना नयी सोच है। बिहार में गरीब गुरबा ने सरकार बनाने का काम किया है इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा हे कि नल से पानी दो । चापाकल में तो बकरी , माल-भैंस मवेशी बांधकर और उनको चराने का काम लोग कर रहे हैं । चापाकल की योजना बंद कर दी गयी है यह तो बहुत अच्छा काम हुआ है । सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है कि आज घर घर तक नल से पानी देने का काम किया है । 7 निश्चयों के माध्यम से बिहार में विकास का काम सरकार कर रही है । मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है लेकिन विपक्ष के लोग हल्ला करके सदन को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं । सरकार द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है तो इनलोगो को खल रहा है । सरकार द्वारा चापाकल को बंद करने का निर्णय लिया गया है यह अचछी सोच है , यह सही सोच है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, पीरपैती विधान सभा में ंपीरपैती और कहलगांव प्रखंड में मनरेगा का काम चल रहा है । हर पंचायत में यह काम कराने का निर्णय

है लेकिन कुछ ऐसी पंचायत है जहां मनरेगा के माध्यम से भवन बनाने का काम किया जाय । मनरेगा के कर्मचारी आवास बनाने का काम किया जाय । आपने बोलने का समय दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ ।

टर्न–17/विजय/15.3.16

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): जनता दल (यूनाइटेड) श्री चन्द्रसेन प्रसाद।

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, आपने बोलने का जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास पर बोलने के लिए मिला है । इस अवसर पर हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ।

महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा होनी है और चर्चा हो रही है हम कहना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार के गरीबों के लिए वरदान है । जब गरीबो के लिए वरदान है तो हमारे विरोधी दल के लोग इस पर चर्चा में बाधा डालने के लिए हल्ला कर रहे हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये गरीबों का भलाई नहीं चाहते, ये बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास नहीं देखना चाहते । ये ग्रामीण इलाकों से चुनकर नहीं आते महोदय । ना इनको पानी की जरूरत है, न इनको शौचालय की जरूरत है, न इनको सड़क की जरूरत है । ये जो हैं शहरों में रहने वाले लोग चर्चा में बाधा डालने का काम किया है । हम कहना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार में अनोखा विकास किया है । जहां तक मनरेगा का सवाल है मनरेगा के सवाल पर ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार में जो प्रोग्रेस किया है वह एक उदाहरण है । ग्रामीण विकास के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार में सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन आया है । मनरेगा बिहार सरकार और केन्द्र सरकार के कोआर्डिनेशन से बना है और यह ग्रामीण विकास का देन है । ये लोग बिहार का विकास नहीं चाहते । ये लोग बिहार का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं । ग्रामीण विकास विभाग का जहां तक वद्धावस्था पेंशन का सवाल है बिहार में वृद्धावस्था पेंशन के सवाल पर जो परिवर्तन आया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बनी तो गरीबों के लिए नीतीश कुमार ने वृद्धावस्था पेंशन में परिवर्तन लाया है । वैसे गरीब जो नहीं

चल सकते थे, जो काम नहीं कर सकते थे और वृद्ध हो गये थे उनके लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया । मैं आपसे कहना चाहता हूं महोदय कि आज ग्रामीण विकास विभाग जीविका के मामले में पूरे देश में एक उदाहरण पेश करने का काम किया है । जीविका बिहार में गरीब महिलाओं को उपर उठाने का काम किया है । बिहार में ग्रामीण विकास द्वारा बिहार के मजदूरों के लिए खासकर महिलाओं के लिए एक परिवर्तन लाने का काम किया है । परिवर्तन इस रूप में कि जीविका नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पूरे देश में जीविका का कोई नाम लेने वाला नहीं था । महोदय, जीविका ऐसी चीज है जो महिलाओं को रोजगार देने का काम करता है । जीविका जो है पूरे बिहार में एक अनोख काम किया है महोदय । इतना ही नहीं जीविका के माध्यम से बिहार पूरे देश में अपना छाप छोड़ने का काम किया है । केन्द्र सरकार ने भी इसका अनुसरण किया है । पांच राज्यों में

(व्यवधान)

उन्होंने उनको प्रशिक्षण दिलाकर जीविका के माध्यम से बिहार के महिलाओं को रोजगार मिला है । ग्रामीण विकास विभाग पूरे बिहार में एक परिर्वन के दौर से गुजर रहा है । यह जो परिर्वतन आया है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में परिवर्तन आया है और पूरे बिहार में पूरे देश के पैमाने पर काम दिखाने का काम किया है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

ग्रामीण विकास विभाग घर घर पानी, शौचालय, घर घर गली, सड़क, नाली पूरे बिहार में निरीक्षण करके बिहार में शहर के जगह गांवों में ग्रामीण विकास विभाग अपना छाप देने का काम किया है । यही हम कहना चाहते हैं । ग्रामीण विकास विभाग गरीबों के लिए एक से एक योजनाएं देने का काम किया है जो काबिले तारीफ है । माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो ग्रामीण विकास विभाग का जो कार्य था जो कार्यशाली थी उसमें सुधार लाने का काम किया है । समिति बनाने का काम किया और आज ग्रामीण विकास विभाग पूरे देश के पैमाने पर उदाहरण बनते जा रहा है । यही हम कहना चाहते हैं । महोदय, हम आपके माध्यम से विरोधियों से कहना चाहते हैं कि ये बिहार का विकास नहीं चाहते, ये बिहार का विनाश देखना चाहते हैं । ये गांव में रहने वाले लोग नहीं हैं ये शहरों में आकर बिहार को बरबाद करना चाहते हैं महोदय । इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि इन विरोधियों का मुंह काला हो गया है। आने वाले चुनाव में इनको जाने का रास्ता नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी के सात

निश्चय को शुरू होने के पहले ये लोग चाहते हैं पांच साल पूरा बरबाद हो जाय । लेकिन हमलोग पूरी तरह एकजुट हैं । सात निश्चय को लागू कर दम लेंगे । यही हम कहना चाहते हैं महोदय । हम विरोधियों का मुकाबला काम से करेंगे । माननीय नेता नीतीश कुमार जी काम में विश्वास रखते हैं । 7 निश्चय में जहां तक पानी का सवाल है,चाहे शौचालय का सवाल हो, चाहे सड़क का सवाल हो इन सवालों पर आगे बढ़ने का काम काम किये हैं । विकास पुरूष नीतीश कुमार जी की जो तारीफ है पूरे देश में हो रहा है, विदेशों में हो रहा है । एक तरफ केन्द्र सरकार कहती है कि हम नीतीश कुमार के मॉडल को अपनाने का काम करेंगे । एक तरफ विरोधी दल के लोग इसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं । हम कहना चाहते हैं कि आज जब ग्रामीण विकास विभाग के मुद्दे पर बहस हो रहा है तो विरोधी दल उसको सुनना नहीं चाहते । विरोधी दल उसको समझना नहीं चाहते । इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं सात निश्चय में चापाकल योजना को बंद करना सरकार के लिए सही कदम है महोदय । यही हम कहना चाहते हैं । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जब सरकार ने निश्चय किया है कि हम घर घर को नल का पानी देंगें तो चापाकल की क्या जरूरत है ? क्या भैंस बांधने के लिए, बकरी बांधने के लिए, घरों में गाड़ने के लिए चाहिए ? इसकी क्या जरूरत है महोदय ।

क्रमशः

टर्न–18/बिपिन/15.3.2016

(व्यवधान)

श्री चन्द्रसेन प्रसादः क्रमशः चापाकल से बढ़िया है नल का पानी । नल का पानी तीन सौ फीट से, चापाकल का पानी डेढ़ सौ फीट से । महोदय, हर दृष्टिकोण से चापाकल बढ़िया है । इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये विरोधी लोग माननीय नीतीश कुमार के विकास और 7 निश्चयों से घबरा कर अनबैलेंस हो गए हैं । यही हम कहना चाहते हैं। विरोधी लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी । आपलोग अगली बार चुनाव में जाइएगा तो आपको गांव में घुसने नहीं देगा, महोदय, यही हम कहना चाहते हैं । महोदय, आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है । ये लोग आरक्षण विरोधी हैं महोदय । एक तरफ भागवत जी कहते हैं कि इन्दिरा आवास में भारत सरकार ने जो कटौती किया

है इसकी चर्चा की । पूरे बिहार के साथ जो सौतेलेपन का व्यवहार किए हैं, बिहार के साथ जो इन्दिरा आवास का ढाई सौ करोड़ राशि का जो किया है, वह काफी है महोदय । यही हम कहना चाहते हैं । इन्दिरा आवास के सवाल पर मोदी जी कहने का काम किए थे कि बिहार में सभी को छत देने का काम करेंगे । इन्होंने जब चुनाव जीतने का काम किया तो ये लोग जुमलावादी बता कर गरीबों के साथ अन्याय किए महोदय । यही हम कहना चाहते हैं । महोदय, इसीलिए ग्रामीण विकास विभाग एक गभ्भीर विभाग है और माननीय श्रवण कुमार जी, जो हमारे बिहार के मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में विकास का राग गूँज रहा है । यही हम कहना चाहते हैं । विरोधियों के पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हल्ला, हल्ला, हल्ला । हल्ला कर-करके ये विरोधी लोग क्या कहना चाहते हैं ? यही कहना चाहता हूं । विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है । ये लोग सिर्फ सदन को बरखास्त करना चाहते हैं । ये लोग पानी-पानी हो गए और कोई गुंजाइश नहीं है । इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये लोग घबरा गए हैं और पानी-पानी हो गए हैं । इनलोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ हल्ला कर रहे हैं । इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लालू यादव के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा और सातों निश्चय पर होगा और यही हमारे माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरा सत्ताधारी, हमलोग एक हैं और नीतीश कुमार, लालू यादव के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलेंगे, सोनिया गांधी के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलेंगे । यही हम आपसे कहना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से केन्द्र बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है, इसका कोई पता नहीं है । अरे, आप पहले बिहारी हैं, तब किसी पार्टी के हैं । आपको बिहारियों के साथ अपनत्व होना चाहिए था लेकिन आप लोग बिहारियों को धोखा देने का काम किए हैं । महोदय, यही हम कहना चाहते हैं । आज बिहार की सरकार जिस तरह से दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, चाहे जितना सवाल आए, चाहे सुरक्षा का सवाल हो, चाहे पेंशन का सवाल हो, चाहे जीविका का सवाल हो, इन सारे सवालों पर ग्रामीण विकास विभाग एकजुट है और काम करेगी । यही हम कहना चाहते हैं ।

अंत में, बिहार के विकास की गाड़ी रूकने वाली नहीं है । आप लोगों के इस हरकत से बंद होने वाला नहीं है । बिहार की गाड़ी बढ़ती रहेगी महोदय । यही हम कहना चहते हैं आपके माध्यम से । हम आपके माध्यम से बताना चाहते

हैं कि जब 2019 का जो लड़ाई है तो नीतीश कुमार अगले प्रधान मंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होने वाले हैं महोदय और उससे घबरा कर वे लोग बौखला गए हैं और पानी-पानी हो गए हैं और पानी का सवाल उठाकर ये लोग ग्रामीण विकास विभाग से घबरा गए हैं । हम विरोधी दल के नेता से कहना चाहते हैं कि आप अपने सदस्यों को समझाने का काम करिए, सदन की मर्यादा को समझाने का काम करिए कि सदन जब तक नहीं चलेगा, तो बिहार कैसे विकास करेगा । महोदय, आपके माध्यम से विरोधी दल के नेता से कहना चाहता हूं कि बिहार के विकास के सवाल पर एकजुट होकर संसदीय प्रणाली बचाते हुए एकजुट होकर बिहार के विकास की जरूरत है महोदय ।

महोदय, अंत में हम कहना चाहते हैं कि ऐ विरोधी दल के लोग, नीतीश कुमार और लालू यादव से घबराने की जरूरत नहीं है । अगला प्रधान मंत्री नीतीश कुमार होगा । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं । जय हिन्द, जय भारत ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मंत्री, श्रम विभाग ने हस्तक्षेप की अनुमति मांगी हैं । मैं उन्हें अनुमति देता हूं । माननीय मंत्री, श्रम विभाग ।

श्री विजय प्रकाश: माननीय महोदय, आज सदन में श्रम संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट संबंधी अभिभाषण को प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला । मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और अपार हर्ष महसूस कर रहा हूं । इसके लिए माननीय महोदय को आज हम आपको सदन से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ में सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते है । सदन में आज पहले दिन मुझे मौका मिला और आपलोगों के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहते हैं ।

साथ-ही-साथ, आज जो यह माहौल सदन में देखा जा रहा है, जो हकीकत सामने आया है वह शोभनीय नहीं है । ये सदन को अच्छे तरीके से चलाने में नाकामयाबी बी.जे.पी.के लोग कर रहे हैं । आज महागठबंधन को जो अपार बहुमत आया हुआ है, उसको देखकर बी.जे.पी. के भाइयों में डर समाया हुआ है और झूठे-झूठे बातों को लेकर पेपर के माध्यम से आना चाहते हैं । हम, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो सात निश्चय का वादा किए हैं और आदरणीय उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ हमलोग उनके नेतृत्व में चलने का जो वायदा किए, आज पूरा बिहार लालायित है, देख रहा है कि जो आदरणीय नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव और सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू

यादव ने जो वादा किया है, उस वायदे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और हमलोग का निश्चय है कि उस वायदे को आगे बढ़ाया जाएगा और 7 निश्चय पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं, परिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं कि जनता के बीच में हम जो वायदा किए हैं, उस वायदे को पूर्णरूपेण निभाने का काम करेंगे और निभाने के लिए अक्सर प्रयास कर रहे हैं । आज जो भाजपा सरकार है, जो ठगने वाली सरकार है, जो जुम्लेवाजी करने वाली सरकार है, जो देश को गुमराह करके राज्य में आने का काम किया है, आज दो साल पूरा होने वाला है, एक भी काम नहीं किया है । बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का काम नहीं किया । आज जो गरीबों को कहा गया था कि हरेक खाता में 15लाख रूपया दिया जाएगा, ऐसा डपोरशंखी सरकार, जो वायदा करने वाले, जो विकास करने वाली सरकार है, उनको चलने नहीं दिया जाता है सदन में । इसलिए हमलोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसा करने वालों को पता नहीं है कि सदन की गरिमा क्या कहलाती है, इसलिए हम, माननीय महोदय, आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो बाल मजदूरों को शोषण से बचाने का सभी उपाय, कल-कारखानों और मजदूरों का अधिकार सुरक्षा अन्य राज्यों में अध्ययन कराकर श्रमिकों के कल्याण एवं बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का अभियान चलाया जाएगा । उनलोगों को रोजगार का अवसर देकर बिहार से गरीबी दूर करने के लिए, पिछड़ापन दूर करने के लिए बिहार में असीम संभावनाएं हैं । मधुबनी पेंटिंग, चांदी की कारीगरी, कालीन बुनाई, भागलपुरी सिल्क, हस्तकरघा स्थानीय बुनकरों के माध्यम से बढ़ाई जाएगी । ... क्रमशः

(व्यवधान)

टर्न-19/राजेश/15.3.15

श्री विजय प्रकाश, क्रमशः- हमारे समाज में यह विडंबना है कि लोग कंपनी के नाम को जानते हैं लेकिन जो श्रमिक हैं, जो काम करके बड़े-बड़े बिल्डिंग को खड़ा करता है, उनका नाम कोई नहीं जानता, इसलिए हम आपके माध्यम से और योजना के माध्यम से, यह बताना चाहते हैं कि बिहार का मजदूर मजदूरी कर सकता है लेकिन उसे कोई मजबूर मानेगा, तो यह श्रम संसाधन विभाग मानने वाला नहीं है, मजदूर मजदूरी कर सकता है लेकिन वह मजबूर नहीं हो सकता है, इसलिए श्रमिकों की दक्षता, विकास, श्रम प्रशिक्षण के लिए, उनके बच्चों के लिए सहायता लागू करना, बाल श्रमिकों के लिए प्रत्येक प्रखंडों मे बधुआ मजदूरी की कुप्रथा से दूर रखने के लिए, बीड़ी मजदूर जो हमारे इलाके के मजदूर है, उनलोगों के गृह निर्माण के लिए

45 हजार रुपये दिये जाते हैं, अब उन्हें गृह निर्माण के लिए एक लाख रुपये देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा सहमति ली गयी है, केन्द्र सरकार से भी अंशदान जारी करने का अनुरोध किया गया है, असंगठित मजदूर श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए, इसके अतिरिक्त राज्य के श्रमिकों के कल्याण हेतु कम-से- कम शिविरों का आयोजन करके बंधुआ मजदूर पुर्नवास योजना, श्रमिक पुर्नवास केन्द्र सुढ़ृढ़ीकरण योजना, अन्तर्राज्यीय प्रवास मजदूर योजना तथा बिहार सरकार के असंगठित कार्य क्षेत्र के कामगार तथा सामाजिक सुरक्षा के तहत कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में उद्योग-धंधा को पनपने की सुविधा है, इसके लिए समय की मांग के अनुरुप श्रम कानून में किये गये कल कारखानों को लाईसेंस निर्गत करने का, निरीक्षण करने का, ऑनलाईन व्ववस्था किया गया है, ऐसे उद्यमियों को सहुलियत होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। महोदय, श्रम संसाधन विभाग का दूसरा पक्ष हम सभी मजदूरों को आने वाले दिनों में हमारे विभाग का प्रयास होगा कि मजदूरों का हुनर, उसकी अभिव्यक्ति का, रोजगार का और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं, आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सात निश्चय किया है, उस सात निश्चय में एक आर्थिक हल युवाओं पर बल, हर अनुमंडल में कम से कम एक-एक आई0टी0आई0 खोलने का जो वादा किया गया है और हर जिला में एक आई0टी0आई0 महिला का जो खोलने का निर्णय लिया गया है और प्रखंड के स्तर पर 12वीं पास युवा को कम्प्युटर तथा उनके प्रशिक्षण देने हेतु सरकार ने उद्धेश्य रखा है, यह बिहार को मजबूत बनाना और अंग्रेजी भाषा का जो है, उसको बढ़ाने के लिए इसमें किया गया है, राज्य में युवाओं को रोजगार को बेहतर रुप से बनाने के लिए स्वतंत्र लाभकारी, ऑटोनोमस के रुप मे, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, बिहार सोशल मिशन की स्थापना की गयी है जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों में सोशल विकास कार्यक्रम की कार्रवाई व्यापक स्तर पर करते हुए 317 में .....(व्यवधान)

एक लाख युवक, युवती के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसीतरह से सांसारिक जीवन बीमा योजना अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा मुह्हैया कराये जाने के लिए 2017 में 12 करोड़ 77 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, ऐसे 18 चिकित्सालय चालू किया गया है, दो-दो पदाधिकारी पटना और मुजफ्फरपुर में पदस्थापित भी हैं, हम मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए ढृढ़संकल्पित हैं, केन्द्र सरकार से अपेक्षित एवं अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास हमलोग करेंगे, केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ जिस प्रकार की

उदासीनता दिखायी है, उसको खत्म करने की हमारी उम्मीद है। योजना मद में श्रम पक्ष अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याण हेतु ग्राम प्रशिक्षण शिविर योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, बाल श्रमिक सुढ़ीकरण योजना, अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना एवं बिहार शताब्दी एवं संगठन में, 44 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रशिक्षण पक्ष में, आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण एवं बिहार कौशल विकास मिशन में आई0टी0आई0 की स्थापना इत्यादि में 681 करोड़ 76 लाख, 48 हजार रुपये तथा नियोजन पक्ष में 39 करोड़, 90 लाख रुपया तथा सरकार के पक्ष में काम करने के लिए 15 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, सभी माननीय सदस्यों के बीच श्रम संसाधन विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 16-17 के रखे हैं.....(व्यवधान)

महोदय, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो केन्द्र में भाजपा की सरकार बैठी है, वह हमारी सरकार की भावना एवं भाव के साथ अनदेखी कर रही है। केन्द्र में जो डपोरशंखी सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है, जो वादा करके केन्द्र की सत्ता में आयी, आज वह वादाखिलाफी कर रही है लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार को चमकाना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके विकास को केन्द्र में बैठी सरकार रोकना चाहती है, हमारे युवा नेता, माननीय उपमुख्यमंत्री जी है, वे भी बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं लेकिन ये भाजपा के लोग विकास कार्य को रोकना चाहते हैं, विकास के रथ को रोकना चाहते हैं, जिसतरह से ये लोग जुमलेबाजी करके, देश को दिग्भ्रमित करने का काम किया, आज भाजपा के हमारे साथी, हमारे भाई, जिसतरह से इस सदन को भी दिग्भ्रमित करने का काम किया है, वह जनता सब देख रही है, आने वाले दिनों में जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जयहिन्द, धन्यवाद ।

अध्यक्षः- माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।

श्री श्रवण कुमारः- अध्यक्ष महोदय, आज सदन में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, ग्रामीण विकास विभाग गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है और इस विभाग की चर्चा पर जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और अपना बहुमूल्य सुझाव से विभाग को अवगत कराने का काम किया है, माननीय श्री नीरज कुमार सिंह जी, माननीय श्री निरंजन कुमार मेहता जी, माननीय श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी, माननीया श्रीमती रेखा देवी जी, माननीय श्री विनोद प्रसाद यादव जी, माननीय श्री मदन मोहन तिवारी जी, माननीया श्रीमती कविता कुमारी जी, माननीय श्री अमित कुमार जी, माननीय श्री मुन्ना कुमार जी, माननीय श्री महबूब आलम जी, माननीय श्री हेमलाल साह जी,

माननीय डा0 शमीम अहमद साहब, माननीय श्री अचमित ऋषिदेव जी, माननीय श्री रामविलास पासवान जी और माननीय श्री चन्द्रसेन प्रसाद जी, कुल 15 माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहॉ पर रखें हैं ग्रामीण विकास के बारे में और उन्होंने चिंता जाहिर किया है महोदय और राज्य के विकास के बारे में चिंता जाहिर किया है महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिहार की सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे गठबंधन की जो सरकार है बिहार में, वह पूरी तरह से बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए गरीबों की योजना को पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्व है। महोदय, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। विगत पॉच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में गॉव के समग्र विकास और सात निश्चय के जरिये बिहार की तरक्की करना चाहते हैं, बिहार का विकास करना चाहते हैं और माननीय नेता नीतीश कुमार जी और गठबंधन के नेताओं की प्राथमिकता है कि राज्य की तरक्की, राज्य का विकास, गॉव का विकास, गॉव के गरीबों का विकास और खासकर ग्रामीण विकास विभाग जो गरीबें से जुड़ा हुआ विभाग है महोदय, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ। माननीय विपक्ष के जो हमारे नेता है, इनको साहस नहीं है, ये कटौती तो लाते हैं लेकिन कटौती पेश करने का भी साहस नहीं है महोदय और न ही सरकार की बातों को सुनने का साहस है और आज ये लोग पानी के लिए सदन में आवाज उठा रहे हैं महोदय, मैं तो कहना चाहता हूँ कि सरकार ने 7 निश्चय के द्वारा इसका खुलासा किया है और कहा है कि पॉच वर्षों में हम बिहार की जनता को नल का पानी पिलायेंगे।

क्रमशः

टर्नः 20 /कृष्ण/15.03.2016

श्री श्रवण कुमार : (क्रमशः) जब बजट पेश हो रहा था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का तो इनको यह सवाल पूछना चाहिये था । यह सवाल इनको उठाना चाहिए था । लेकिन इनको फुर्सत नहीं है । इनको मतलब नहीं हैं । इनको सदन चलाने का मकसद नहीं है । इनको सिर्फ हरिओम करना है । इनको सिर्फ चाहिए कि जनता जाने कि हम जनता के राज्य के सवालों के लिये चिन्तित है । इनके मन में गरीबों के लिये चिन्ता नहीं है । महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज महबूब आलम साहब ने एक सवाल उठाया था कि बिहार में जो मजदूर हैं, मजदूरों का जो न्यनतम मजदूरी है, 177/–रू0 हम देते हैं, भारत सरकार मात्र हमको 162/–रू0

देती है । भारत सरकार के माननीय मंत्री,ग्रामीण विकास विभाग श्री चौधरी विरेन्द्र सिंह जी से मैं मिला था और राज्य में मजदूरों की मजदूरी में एकरूपता नहीं है, इसके लिए उनसे मैं आग्रह किया था और बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए था महबूब साहब को कि भारत सरकार माात्र 162/-रू0 देती है और हम 177/-रू0 देते हैं यानी राज्य के खजाने से प्रति मजदूर 15/-रू0 ज्यादा मजदूरी बिहार के मजदूरों को देते हैं । महोदय, इनको तो बात सुनना चाहिए था । जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था तो इनका तेवर बढ़ा हुआ था और लगता था कि बिहार के ये ही मालिक हैं, बिहार में ये ही विकास कर सकते हैं और ये चुनौती देते थे लोक सभा के चुनाव के बाद । हुआ क्या महोदय, जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था तो ये बार-बार आंकड़े पेश करते थे । कहते थे कि 190 विधान सभा में एनडीए नंबर-वन पर गया और यह गुमान था इनको कि 190 विधान सभा में ये प्रथम स्थान पाये थे तो लगता था कि बिहार इनके तरफ है । लेकिन जो लोक सभा का चुनाव हुआ था, उस समय फरेब पर आधाारित, झूठ पर आधारित, असत्य पर आधारित, जुमलबाजी पर आधारित बातों को ले करके बिहार के लोगों को भरमा कर वोट लेने का काम किया । उसमें सच्चाई नहीं थी, अगर सच्चाई होती तो विधान सभा के चुनाव के जो नतीजे आये हैं, उनसे सबक लेना चाहिए, इनको सीखना चाहिए ।

(व्यवधान)

बिहार की जनता इंतजार कर रही थी कि कब इनको जुमलेबाजी का जवाब दें । कब इनको असत्यता का जवाब दें । कब इनके फरेबबाजी का जवाब दें और बिहार की जनता ने इनको जवाब दिया । बिहार ही नहीं, देश की जनता को कहा था 15 से 20 लाख रूपया हर गरीब के खाते में चला जायेगा । गांव के जो गरीब लोग हैं, जो इन्दिरा आवास पर निर्भर हैं, उन्होंने सोचा की एक बार अगर 15 से 20 लाख रूपया हमारे खाते में चला आयेगा तो हमारा किस्मत बदल जायेगा । लेकिन वह यह नहीं जानता था, उनको यह नहीं मालूम था, ये जो दिल्ली में लोग बैठे हैं वे सत्य नहीं बोलते हैं । सत्य से उनका कोई रिश्ता नहीं है । वे जुमलाबाजी करते हैं । यह मैं नहीं कह रहा हूं । यह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने प्रेस और मीडिया के सामने कहा कि लोक सभा चुनाव के समय जो बाते कही गयी, वह जुमलाबाजी था ।

(व्यवधान)

जो हालत अभी कर रहे हैं अगर यही हालत रहा तो उस समय यहां की जनता ने इनको 53 सीट पर लाकर बैठा दिया । अगर यही हालत रहा तो बिहार की

जनता इनको जीरो पर लाकर बैठायेगी । इनको बिहार की जनता बखशने वाली नहीं है । महोदय, बिहार में भाजपा के बड़े नेताओं ने घुम-घुम कर एलान कर दिया कि विधान सभा चुनाव से पहले कि बिहार कीं विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे । देश के प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं और सवा सौ करोड़ की घोषणा करके जाते हैं, उसमें भी बिहार को एक छदाम नहीं मिलता है । ये जुमलाबाजी करनेवाले लोगों को बिहार की जनता सबक सीखाने का काम करेगी।

(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार में इनके पास कोई नेता नहीं है । ये गुजरात का नेता ला रहे हैं । बौरो प्लेअर लाकर महोदय, बिहार में खेलना चाहते हैं । बिहार में बौरा प्लेअर नहीं चलेगा । गुजराती नेता नहीं चलेगा । बिहार में बिहारी नेता चाहिए । आपको मैं बताना चाहता हूं । महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी एक महत्वकांक्षी योजना है, राज्य के 564 प्रखंडों में जीविका के माध्यम से हम स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं । गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले गांवों की महिलाओं को इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनको स्वरोजगार से जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं । सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब तक राज्य में 4 लाख 60 हजार स्वयं सहायता समूह का हमने गठन किया है और 31 मार्च, 2016 तक 5 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे । 2017-18 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य हमने रखा है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और राज्य में डेढ़ करोड़ वैसे परिवार गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं, उनको हम स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको रोजगार देंगे ओर उसको आत्म निर्भर बनाने का काम करेंगें, यह राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी । महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलायें सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनेगी, आज गांव की जो महिलायें, गांव के जो गरीब लोग जो महाजन पर आश्रित थे, जो बड़े लोगों पर आश्रित थे, जो उनसे कर्ज लेते थे, 10रू0 सैकड़ा, 30 रूपया सैकड़ा, 50 रूपया सैकड़ा, हम जहां-जहां बनायेंगे, हम उनको दो रूपये सूद पर राशि देंगे । उनकी भलाई के लिये उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये, उनके घरेलू काम के लिये उनको पैसा मिलेगा और उसके लिये बैंक में नहीं जाना है, उनके घर पर ही इंतजाम उनके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होगा ।

महोदय, बिहार में जब महिला उत्थान की बात करते हैं ।

(व्यवधान)

टर्न-21/सत्येन्द्र/15-3-16 .

(व्यवधान जारी)

श्री प्रेम कुमार: महोदय,पूरे राज्य में पानी का संकट है और यह सरकार गरीब विरोधी सरकार है। महोदय,यह सरकार जनविरोधी सरकार है।(व्यवधान जारी)यह सरकार जनता को पानी नहीं देना चाहती है। सरकार जवाब देने से महोदय भाग रही है। विधायक कोटे को बंद करने की साजिश सरकार कर रही है।(व्यवधान जारी)लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने पिछले वार भी विधायक कोटा को समाप्त किया था। यह सरकार नहीं चाहती है कि राज्य की जनता को शुद्ध पानी मिले। पूरे राज्य में महोदय जहर का पानी मिल रहा है।(व्यवधान जारी) हजारों चापाकल महोदय बंद है।(व्यवधान जारी)विधायकों का जो मुख्यमंत्री चापाकल योजना था(व्यवधान जारी)

जल ही जीवन है। हर मनुष्य के लिए चाहे वो गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो(व्यवधान जारी)हजारों चापाकल बंद पड़े हुए हैं।(व्यवधान जारी) यह सरकार नहीं चाहती है कि बिहार की जनता को शुद्ध पेयजल मिले इसलिए हमलोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री श्रवण कुमार: गरीबों का जो लक्ष्य था 2 लाख 80 हजार महोदय उसको काटकर के 2 लाख 33 हजार कर देते हैं । यह भारत सरकार की सोच है महोदय। भारत सरकार कहती है कि 2022 तक हम हर गरीब को इन्दिरा आवास पहुंचायेंगे। कैसे पहुंचाईयेगा देश के प्रधानमंत्री जी, कैसे पहुंचाईयेगा भारतीय जनता पार्टी के नेता जी,आपको बताना पड़ेगा कि 2022 तक आप कैसे पहुंचाईयेगा? जो सर्वेक्षण आर्थिक समाजिक और जातिगत जनगणना बिहार में हुए है उसके हिसाब से बिहार में 90 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको सर छिपाने के लिए छत नहीं है और भारत सरकार कहती है, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय कहता है कि हम 2022 तक सबको घर देंगे । जब हम हिसाब जोड़ते हैं तो लगता है कि 35-40 साल से ज्यादा बिहार के गरीवों के घर बनाने में लगेंगे । महोदय,अगर भारत सरकार का निश्चय सही है तो इनको कम से कम बिहार के लक्ष्य को बढ़ाना पड़ेगा अगर लक्ष्य नहीं बढ़ाते हैं तो इन्होंने 2022 का जो समय सीमा तय किया है उस समय सीमा को बढ़ाना पडेगा । देखिये महोदय,क्या हुआ,इनके बिहार के कोटे से 7-7 मंत्री हैं दिल्ली में , महोदय जब हवाई जहाज से पटना आते हैं,हवाई जहाज से एरोड्राम पर उतरते हैं, बिहार के गरीबों का, बिहार के खेतों का, खलिहानों का

चिन्ता इनके मन में सताता है लेकिन वही मंत्री जो दम भरते हैं बिहार में आकर अगर दिल्ली में बिहार के सवालों को भारत सरकार के सामने रखते और भारत सरकार के सामने अपने क्षेत्र का सवाल भी रखते महोदय तो बिहार के गरीबों के साथ नाईंसाफी नहीं होता। वर्ष 2012-13 में बिहार को 6 लाख 86हजार 365 आवास स्वीकृत हुआ। महोदय,वर्ष 2013-14 में 5 लाख 52 हजार 837 और 2014-15 में 2 लाख 96 हजार 06 और 2015-16 में 2 लाख 33 हजार 546 है महोदय। इनका लगातार कोटा घटते जा रहा है। गरीबों के हमदर्द वाली सरकार चाय बेचने वाला का बेटा गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है और गरीब का हिस्सा काटता चला जा रहा है यही है महोदय इनको गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं है । बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया तो लगातार कोटा घटा रहे हैं। इसी प्रकार महोदय,हम बिहार में इन्दिरा आवास के लाभुकों को सीधे इलेक्ट्रोनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम से उनको पैसा देते है। जो गरीब हैं उनको सीधे खाते में पैसा भेजने का काम करते है। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हमने आधार कार्ड बनाने का फैसला लिया है लगभग 6करोड़ 63 लाख लोगों का आधार कार्ड बन गया है शेष का कार्ड जल्द ही बन जायेगा। इसी प्रकार से महोदय अभी तक भारत सरकार कितना असंवेदनशील है गरीबों के प्रति कि अभी तक 2014-15 का हमें द्वितीय किस्त कई जिलों का नहीं मिला और 2015-16 का प्रथम किस्त भी हमको नहीं मिला,कितना भारत सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील है महोदय ये उनके आंकड़े में पता चलता है। इन्दिरा आवास में महोदय,लगभग 2524 करोड़ रू0 हमारा बिहार का बकाया है वो भी हमको नहीं मिल रहा है। यही गरीबों के प्रति संवेदनशील सरकार है महोदय। महोदय,आपसे मैं कहना चाहता हूं इसी प्रकार से मनरेगा योजना में हम गरीबों को 100 दिन काम देते हैं पलायन रोकने की योजना है महोदय। मानव दिवस सृजन करते हैं,हम 2015-16 में 5 करोड़ 75 लाख 24243 तथा 200 दिन रोजगार पाने वाले लाभुकों की संख्या लगभग 55323 है महोदय। आज कुल जॉब कार्डधाारियों की संख्या 1करोड़ 30 हजार 19 हजार 174 है,सक्रिय जॉब कार्डधारियों की संख्या 3116712 है और 2015-16 में अबतक रोजगार प्रदान किये गये। कुल परिवारों की संख्या 13 लाख 33 हजार 313 है महोदय। इसी प्रकार महोदय,15-16 में जो मानव दिवस सृजन हुए हैं 5 करोड़ 75 लाख 24243 है महोदय उसी प्रकार 100 दिन काम पाने वाले जो परिवार हैं महोदय 56330 है। वित्तीय वर्ष 15-16 में वृक्षारोपण बगैरह जो हुई है उसके बारे में इसमें डिटेल है महोदय। महोदय,आपसे कहना चाहते हैं कि भारत सरकार की एक नीति जो है वह एकरूपता नीति नहीं है जिसके चलते मजदूरों का भी मजदूरी एकरूप नहीं है। हमें

सदन को बताते हुए प्रसन्नता होती है महोदय कि मनरेगा में एक हजार आंगनबाड़ी केन्द्र बनायेंगे । राज्य के सभी दलित महादलित टोलों में पक्की गली नलियों का निर्माण करेंगे। प्रत्येक पंचायत में राजीव गांधी सेवा केन्द्र का भी निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महोदय,वित्तीय वर्ष 15-16 में हमारा गांव हमारी योजना के जरिये राज्य के 8411 पंचायतों में, बार्डों में हमने 10-1-16 से हमने 5-1-16 तक जनजागरण चलाकर मनरेगा श्रम बजट वार्षिक योजना 2016-17 के लिए स्टेट रूलर डेवलपमेंट प्लान राज्य ग्रामीण विकास योजना तैयार किया है। इसमें हमने अपने मंत्रियों से माननीय विधायकों से भी अनुरोध किया था जिसमें माननीय विधायकों और माननीय मंत्री और राज्य सभा के सदस्य और माननीय माननीय जो बिहार कोटे से मंत्री हैं उनसे आग्रह किया था महोदय। इसी प्रकार से महोदय हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसमें मैंने भारत सरकार के माननीय मंत्री से मिला था। माननीय सांसदों से 53 गांव की सूची प्राप्त हुई है राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से जितनी योजनाएं चलायी जा रही है उन योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है महोदय। महोदय,ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री से मिला महोदय तो हमने इसमें जो विसंगतियां थी उसके बारे में उनसे कहा तो माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि जो योजना बनी है। ये योजना भारत सरकार ने जो बनाया है जो योजना बनायी गयी है उन राज्यों को ध्यान में रखकर जहां उद्योग धंधे अधिक हैं । उसी प्रकार से महोदय हम सदन को जानकारी देना चाहते हैं इससे सदन को भी प्रसन्नता होगी महोदय कि राज्य में 77 नये प्रखंड सह अंचल कार्यालय आवासीय परिसर ..

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी,अब माननीय सदस्यों के प्रसन्नता वाली सारी बात जल्दी जल्दी बतला दीजिये समय कम है।

श्री श्रवण कुमारः बनाया जा रहा है। इसकी स्वीकृति दी गयी है साथ ही 101 सूचना प्रोद्योगिकी भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है। पुराने और जर्जर भवनों के स्थान पर नये सूचना प्रोद्योगिकी भवन बना रहे हैं । 925 करोड़ 47 लाख रू0 इस पर व्यय होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन योजना है महोदय इसमें राज्य के 6 स्थानों का चयन किया गया है महोदय। बैरिया (सम्पतचक पटना)नवरंगा(मानपुर गया)कुचिला (कोचस,रोहतास) सोनवर्षा (सहरसा)बरबतपारेशन (पश्चिम चम्पारण) एवं शिवाजीनगर (समस्तीपुर)महोदय, 25 हजार से 50 हजार के बीच की आवादी के शहर और गांव के बीच की जो आबादी है उसको जोडकर के अरबन इलाका बनाया गया है। इसमें 30 प्रतिशत भारत सरकार राशि खर्च करेगी।आधार कार्ड के बारे में हमने पहले बतला दिया है कि आधार कार्ड हम बना रहे हैं और आधार

कार्ड के जरिये सिर्फ और सिर्फ इन्दिरा आवास को नहीं जोड़ेंगे, मनरेगा को नहीं जोड़ेंगे बल्कि राज्य में जितने प्रगतिशील गांव के तरक्की के लिए गांव के विकास की योजना चल रही है उसको भी हम आधार कार्ड से जोड़कर के हम उसमें काम करेंगे। हमारा जो प्रखंड स्तर पर आर0टी0पी0एस0 सेंटर है महोदय, उस सेंटर में भी इसकी व्यवस्था 1 अप्रैल,2016 से पूर्ण रूप से चालू हो जायेंगे। छात्रवृत्ति हो, राशन हो, किरासन हो, मनरेगा हो, इन्दिरा आवास हो उसके लाभूकों को इससे जोड़कर के हम वहां पर काम करेंगे। महोदय,अब सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि गरीब और गांव के विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान के मांगों की स्वीकृति प्रदान की जाय। मेरा वक्तव्य प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाय।

(माननीय मंत्री का क्तव्य परि0–1 द्रष्टव्य)

अध्यक्षः ठीक है। माननीय सदस्यगण, आज ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर कोई कटौती प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है इसलिए मैं माननीय मंत्री के मूल मांग के प्रस्ताव को आपकी स्वीकृति हेतु रखता हूॅ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च,2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 55,10,06,08,000/–(पचपन अरब दस करोड़ छः लाख आठ हजार)रू0 से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण,आज दिनांक 15 मार्च,2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 23 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार,दिनांक 16 मार्च,2016 को 11 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है।

परिशिष्ट-1

अध्यक्ष महोदय,

आज सदन में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गयी। ग्रामीण विकास विभाग राज्य के गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है।

महोदय,

जिन माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव ग्रामीण विकास विभाग को दिये गये हैं, उनके प्रति अभार प्रकट करता हूँ।

हमारी कोशिश होगी कि योजना बनाते समय माननीय के सुझावों को अमल में लाने का प्रयास करूंगा।

महोदय,

विपक्षी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि जब लोक सभा चुनाव का परिणाम आया तो बहुत उत्साहित थे और इसी सदन में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, श्री नन्द किशोर यादव जी ने कहा था कि आने वाले विधान सभा के चुनाव में गुड्डी तरह श्री नीतीश कुमार को उड़ा देंगे। इन्हें लगता था राज्य में विकास हो रहा है तो सिर्फ हमारे भरोसे ही हो रहा है। अंहकार में थे, मदान्ध थे।

अध्यक्ष महोदय,

शायद इन्हें मालूम नहीं था कि लोक सभा के चुनाव का अप्रत्याशित नतीजा असत्य पर अधारित था, जुमलेवाजी पर अधारित था। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। भाजपा के एक बड़े नेता ने मिडिया से अपने साक्षात्कार के समय दिया था।

महोदय,

बिहार की महान जनता इनके जुमला को समझ चुकी थी, समय का इन्तजार कर रही थी। विधान सभा के चुनाव में इन्हें 91 सीट से 53 सीट पर खड़ा कर दिया, तब भी इनकी आदत में सुधार नहीं हो रहा है।

महोदय,

बिहार के लिए जो वादे छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने किया है, उसे पुरा करें, नहीं तो 2019 के चुनाव में दिल्ली भी जायेंगी। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे, वहॉ इनका खाता खुलने वाला नहीं है।

महोदय,

बिहार के पास कोई नेता नहीं, जो बिहार की बागडोर संभाल सके। इनको अपने आप पर भरोसा नहीं है। ये गुजरात से नेता बिहार में ला रहे हैं। यह चलने वाला नहीं है। यह जय प्रकाश नारायण, लोहिया जी, कर्पुरी जी की धरती रही है। बिहार के बेटा को पछाड़ने वाला गुजराती नहीं हो सकता।

एक तरफ श्री नीतीश कुमार और दुसरी तरफ माननीय प्रधान मंत्री जी में मुकाबला बिहार के चुनाव में हुआ। जनता ने श्री नीतीश कुमार, लालू जी एवं राहुल जी के गठबन्धन को चुना। प्रधानमंत्री को बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया। अब भी भाजपा के नेताओं को सबक लेनी चाहिए।

जीविका

अध्यक्ष महोदय,

राज्य भर में 534 प्रखण्डों में जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह गॉव–गॉव में बनाकर राज्य के गरीब एवं गरीबी रेखा से नीचे जिन्दगी बसर करने वाली महिलाओं एवं उनके परिवारों को जोड़ना चाहता हूँ। उनके स्वरोजगार कर उन्हें आत्म निर्भर बनाना चाहता हूँ।

अब तक राज्य में 4 लाख 60 हजार स्वयं सहायता समूहों का निर्माण हो चुका है। मार्च, 2016 तक पॉच लाख एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 तक दस लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। हमें एक करोड़ पचास लाख परिवार को इससे जोड़ना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करना हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई, दवाई एवं अन्य घरेलू कार्यो के लिए महाजन के यहॉ नहीं जाना पड़े। वे सीधे स्वयं सहायता समूह से 2 प्रतिशत की ब्याज पर राशि प्राप्त कर अपना जरूरी कार्य का निपटारा कर सकें।

बिहार में जब महिलाओं के उत्थान एवं उनके सशक्तिकरण क्षेत्र में कार्य आरम्भ करता हूँ तो भारत सरकार अपेक्षित सहयोग नहीं करती है। केन्द्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोजेक्ट एवं आजीविका मिशन में राज्यांश 60/40 प्रतिशत बढ़ा दी गई है जिसके कारण राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ा है एवं योजनाओं के संचालन में बाधा आ रही है ।

अध्यक्ष महोदय,

महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना में भारत सरकार से समय पर राशि प्राप्त नहीं होती है, जिसके चलते योजनाओं के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तथा शिथिलता भी आ जाती है ।

अध्यक्ष महोदय,

जीविका में विगत दो वर्षों के आवंटन एंव विमुक्ति की राशि पर नजर डालें तो निम्न आकड़ों के अनुसार केन्द्र सरकार का रवैया स्पष्ट होता है:–

क0 सं0	वित्तीय वर्ष	आवंटन	विमुक्ति की राशि	बकाया राशि
1	2014–15	415.39 करोड़ (चार सौ पन्द्रह करोड़ उनचालीस लाख) रू0	145.46 करोड़ (एक सौ पैंतालिस करोड़ छियालिस लाख) रू0	269.93 करोड़ (दो सौ उनहत्तर करोड़ तिरानवे लाख) रू0
2	2015–16	269.50 करोड़ (दो सौ उनहत्तर करोड़ पचास लाख) रू0	170.42 करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़	99.08 करोड़ (निनानवे करोड़ आठ

			बेयालिस लाख) रू0	लाख) रू0
			कुल बकाया राशि	**369.01 करोड़ (तीन सौ उनहत्तर करोड़ एक लाख) रू0**

अध्यक्ष महोदय,

उक्त राशि भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में केन्द्र सरकार अपेक्षा अनुरूप दिलचस्पी नहीं ले रही है।

बैंको का सहयोग

विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंको का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है । बैंको में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सहयोग की सराहना करता हूँ। अब तक 80 हजार स्वयं सहायता समूहों को बैंक से लिंक किया जा चुका है। तीन लाख तक ऋण लेने वाले स्वयं सहायता समूह को सात प्रतिशत की सूद का प्रावधान है, लेकिन नियमित रूप से राशि जमा करने पर सूद की दर तीन प्रतिशत हो जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में 23,890 (तेईस हजार आठ सौ नब्बे) युवकों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 7,317 (सात हजार तीन सौ सतरह) युवक रोजगार पाकर आत्म निर्भर बन गये।

वित्तीय वर्ष– 2016–17 में 26 हजार युवकों को प्रशिक्षण देने तथा 13 हजार लोगों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है।

इन्दिरा आवास

अध्यक्ष महोदय,

इन्दिरा आवास योजना केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना गरीबों से जुड़ा है, इस योजना में हर गरीबों को मकान मिले, सरकार इसकी चिन्ता में है, परन्तु केन्द्र सरकार को गरीबों की चिन्ता नहीं है, गरीबों की चिन्ता होती तो केन्द्र सरकार द्वारा इन्दिरा आवास के लक्ष्य में कटौती नहीं होती। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना के अनुसार बिहार में आवास पाने वाले गरीबों की संख्या 90 लाख के करीब है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खुले असमान के नीचे अपनी जिन्दगी परिवार के साथ गुजार रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय,

भारत सरकार द्वारा 2022 तक हर गरीबों को घर की योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित की गयी है। भारत सरकार का लक्ष्य और बिहार को दिये गये आवंटन के अनुसार बिहार के सभी योग्य लाभुकों को आवास उपलब्ध कराने में 35 से 40 वर्ष लगेंगे। भारत सरकार को बिहार के लिए लक्ष्य में बढ़ोतरी करनी होगी या तय समय सीमा को आगे बढ़ाना पड़ेगा तभी गरीब लाभुकों को ससमय आवास की सुविधा मिल पायेगी ।

महोदय,

भारत सरकार में बिहार के कोटा से सात मंत्री है । ये मंत्री जब बिहार आते हैं तो बिहार की चिन्ता बढ़ जाती है, जब दिल्ली चले जाते हैं तो बिहार की चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं।

इन मंत्रियों से जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोकसभा क्षेत्र और वहाँ के गरीबों की चिन्ता करते तो बिहार की हिस्से में कटौती नहीं होती और गरीब अपने हक से वंचित नहीं होते ।

महोदय,

जबसे दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, तब से लगातार बिहार का इंदिरा आवास का लक्ष्य घटता ही जा रहा है।

इंदिरा आवास योजना का विगत चार वित्तीय वर्ष का भौतिक उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृति
2012–13	8,16,305	6,86,365
2013–14	6,05,550	5,52,837
2014–15	2,74,981	2,96,086
2015–16	2,33,546	2,31,788

जब लोकसभा चुनाव के बाद लक्ष्य का निर्धारण 2 लाख 80 हजार किया और जब विधान सभा का प्रचार चुनाव बिहार में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और एन0डी0ए0

बिहार में पराजित हो गयी। बिहार की जनता ने रिजेक्ट/अस्वीकार कर दिया तब गरीबों के इन्दिरा आवास का कोटा काटकर 2 लाख 33 हजार कर दिया। यही गरीबों की हमदर्दी वाली सरकार है, जो गरीबों का हिस्सा काटती है, गरीबों का हक काटती है।

अध्यक्ष महोदय,

इन्दिरा आवास और मनरेगा के लाभुकों को सीधे पैसा उसके खाते में जाय इसके लिए सरकार पारदर्शिता लाने के लिए ई0एफ0एम0एस0 (इलेक्ट्रोनिक फन्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम) के माध्यम से भेजा जाता है। राज्य सरकार ने इस योजना को पारदर्शी बनाने का काम किया है। अब तक राज्य में आधार कार्ड 6.63 करोड़ (छः करोड़ तिरसठ लाख) लोगों का बनाया गया है। शेष कार्ड जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जायेगा, बच्चों का भी आधार कार्ड का निर्माण हो रहा है।

आज भी इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत 9 जिलों यथा–अरवल, भागलपुर, जहानाबाद, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान एवं वैशाली का वित्तीय वर्ष 2014–15 के द्वितीय किस्त तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रथम किस्त की राशि अभी तक भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक भारत सरकार के पास इस योजना का 2534.81करोड़ (दो हजार पांच सौ चौतीस करोड़ इक्कासी लाख) रूपये बकाया है । जिसमें वित्तीय वर्ष 2014–15 के 368 करोड़ एवं 2015–16 के लगभग 635 करोड़ सम्मिलित हैं ।

मनरेगा

अध्यक्ष महोदय,

मनरेगा योजना गॉव के गरीबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से गॉव के गरीब मजदूरों को साल में 100 दिन काम देकर पलायन से रोकने की कार्रवाई की जाती है। राज्य में कुल जॉब कार्ड धरियों की संख्या 1,30,19,174 (एक करोड़ तीस लाख उन्नीस हजाार एक सौ चौहत्तर) है। सकिय जॉब कार्ड धारियों की संख्या 31,16,772 (एकतीस लाख सोलह हजार सात सौ बहत्तर) है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रोजगार प्रदान की गयी परिवारों की संख्या 13,33,333 (तेरह लाख तैतीस हजार तीन सौ तैंतीस) है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में मानव दिवस सृजन 5,75,24,243 (पॉच करोड़ पचहत्तर लाख चौबीस हजार दो सौ तेतालिस) तथा सौ दिन रोजगार पाने वाले लाभुकों की संख्या 55,330 (पचपन हजार तीन सौ तीस) है।

वित्तीय वर्ष– 2015–16	
राज्य में बी0पी0एल0 परिवारों की कुल संख्या	1,26,56,105 (एक करोड़ छब्बीस लाख छप्पन हजार एक सौ पॉच)
कुल निर्गत जॉब कार्ड की संख्या	1,30,19,174 (एक करोड़ तीस लाख उन्नीस हजार एक सौ चौहत्तर)
सकिय जॉब कार्ड धारी की संख्या	31,16,772 (एकतीस लाख सोलह हजार सात सौ बहत्तर)
वर्ष– 2015–16 में अब तक रोजगार प्रदान किये गये कुल परिवारों की संख्या	13,33,313 (तेरह लाख तैतीस हजार तीन सौ तेरह)

वर्ष– 2015– 16 में सृजित किये गये मानव दिवस की संख्या	5,75,24,243 (पॉच करोड़ पचहत्तर लाख चौबीस हजार दो सौ तेतालीस)
वित्तीय वर्ष– 2015–16 में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या	56,330 (छप्पन हजार तीन सौ तीस)
वित्तीय वर्ष– 2015–16 में वृक्षारोपण योजना की संख्या	8,973 (आठ हजार नौ सौ तिहतर)
वित्तीय वर्ष– 2015–16 में कुल वृक्षारोपण की संख्या	17,94,600 (सतरह लाख चौरानवे हजार छः सौ)

महोदय, मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को मजदूरी भारत सरकार मात्र 162 रू0 देती है, जबकि राज्य सरकार 177 रू0 न्यूतम मजदूरी देती है। राज्य सरकार बिहार में मजदूरों को 15 रूपया राज्य के खजाने से देती है। मनरेगा योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का पहले 90 और 10 का अनुपात था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार ने इसे बढ़ाकर 75–25 का अनुपात कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में मजदूरों के मजदूरी में एकरूपता लाने की आवश्यकता है इस हेतु भारत सरकार से अनुरोध करना चाहुँगा कि बिहार सरकार द्वारा निर्धारित कृषि कार्य में लगे अकुशल मजदूरों की भांति मनरेगा मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 189 रूपये की जाय । **महोदय,** भारत सरकार से कहना है कि मनरेगा से 1000 (एक हजार) आगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करना है। राज्य के सभी महादलित टोलों–वसावटों में पक्की सड़क एवं पक्की गलियों का निर्माण

करना है। प्रत्येक पंचायत में राजीव गॉधी सेवा केन्द्र का निर्माण कराने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में वृक्षारोपण योजनाओं की संख्या 8,973 (आठ हजार नौ सौ तिहत्तर), वृक्षारोपन की संख्या 17,94,600 (सतरह लाख चौरानवे हजार छः सौ) है । अब तक राज्य में 11,882 (ग्यारह हजार आठ सौ बिरासी) कर्मियों से कारण पृच्छा किया गया। 3,33 (तीन सौ तेतींस) सरकारी कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा 267 मनरेगा कर्मी को सेवा मुक्त कर 8 करोड़ रूपये की वसूली भी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में हमारा गॉव हमारी योजना के जरिये राज्य में 8,411 (आठ हजार चार सौ ग्यारह) पंचायतों के वार्डों में 10.01.2016 से 5.02.2016 तक जन जागरण चलाकर मनरेगा श्रम बजट वार्षिक कार्य योजना 2016–17 के लिए स्टेट रूरल डेवलपमेन्ट प्लान (राज्य ग्रामीण विकास योजना) तैयार की गयी।

इसकी सूचना पत्र के माध्यम से सभी माननीय मंत्री, सभी माननीय विधायक, सभी माननीय विधान पार्षद, राज्य सभा एवं लोक सभा के सभी माननीय सदस्यों के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्यों को भी व्यक्तिगत तौर पर इस योजना में शामिल होने का अनुरोध भी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

इसके लिए माननीय सदस्यों का कई वार्डों एवं पंचायत स्तरीय बैठक में शामिल होकर अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुआ है ।

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा दिनांक 09.02.16 से 11.02.2016 के बीच कर योजनाओं का अनुमोदन भी किया गया।

प्रखंड कार्यालय भवन एवं आधारभूत संरचना

अध्यक्ष महोदय,

सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में 77 नये प्रखंड–सह– अंचल कार्यालय–सह–आवासीय परिसर–सह–निरीक्षण कमरा के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जा चुकी है । साथ ही 101 सूचना प्रावैद्यिकी भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है । नये भवन तथा पुराने जर्जर भवन के स्थान पर सूचना प्रौवैद्यिकी भवन का निर्माण कार्य कराने की योजना है। अध्यक्ष महोदय, यह योजना नाबार्ड द्वारा वित्तीय सम्पोषित है । इस योजना पर लगभग 935.47 करोड़ (नौ सौ पैतीस करोड़ सैतालीस लाख) रूपये व्यय कर निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है । राज्य अपने बलबूते अपने संसाधन से आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है ।

आधार कार्ड

आधार कार्ड योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 19 दिसम्बर, 2014 से आधार पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया। राज्य में कुल 11 पंजीकरण एजेन्सियॉ चयनित की गयी और उन्हें जिलों का आवंटन किया गया।

आधार कार्ड पंजीकरण का कार्य प्रखण्ड, पंचायत, आगनबाड़ी केन्द्र एवं सामुदायिक भवनों में चल रहा है।

क0 सं0		
1	आधार पंजीकरण का कार्य आरम्भ	वर्ष–2011
2	अब तक आधार पंजीकरण की संख्या	663 लाख (छः करोड़ तिरसठ लाख)
3	आधार सृजन का प्रतिशत	63.74 प्रतिशत
4	0–17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार सृजन की संख्या	1,65,79,687 (एक करोड़ पैंसठ लाख उनासी हजार छः सौ सतासी)
5	18 वर्ष से उपर आयु वर्ग के व्यक्तियों के आधार सृजन की संख्या	4,54,76,853 (चार करोड़ चौवन लाख छिहतर हजार आठ सौ तिरपन)

राज्य में 0 से 17 वर्ष आयु वर्ग के कुल जनसंख्या 4,79,06,508 (चार करोड़ उनासी लाख छः हजार पाँच सौ आठ) में से 1,65,79,687 (एक करोड़ पैंसठ लाख उनासी हजार छः सौ सतासी) तथा 18 से अधिक उम्र वाले कुल जनसंख्या 5,61,92,824 (पाँच करोड़ एकसठ लाख बिरानवे हजार आठ सौ चौबीस) में से 80.93 प्रतिशत व्यक्तियों को आधार कार्ड बनाया जा चुका है। कुल 6,63,00,000 (छः करोड़ तिरसठ लाख) लोगों का आधार कार्ड हेतु पंजीकरण किया जा चुका है। आधार कार्ड निर्माण हेतु प्रखण्ड स्तर पर आर0टी0पी0एस0 सेन्टर में भी इसकी व्यवस्था 1 अप्रैल,2016 से की जा रही है। सरकार का संकल्प है कि छात्रवृति, राशन–किराशन, मनरेगा एवं इन्दिरा आवास पाने वाले सभी लाभूकों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाय।

रूरबन योजना

अध्यक्ष महोदय,

रूरबन योजना के तहत राज्य के 6 स्थानों का चयन ग्रामीण विकास विभाग ने किया है जिसकी सूची भारत सरकार को भेजा दिया गया है।

1. बैरिया (सम्पतचक,पटना)
2. नवरंगा (मानपुर,गया)
3. कुचिला (कोचस,रोहतास)
4. सोनवर्षा (सहरसा)
5. बरबत पारेशण (पश्चिम चम्पारण)
6. शिवाजीनगर (समस्तीपुर)

इसमें 25 हजार से 50 हजार के बीच की आबादी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसका चयन किया गया है। इस योजना के लिये सड़क, बिजली, नाली, पी0सी0सी0 इत्यादि कार्यों के लिए 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार देगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । इसकी योजना पूर्व से तैयार की जा रही है।

भारत सरकार से राशि प्राप्त होते ही कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

अध्यक्ष महोदय,

सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा भारत सरकार द्वारा माननीय सांसदों के सम्मान में की गयी। बिहार के सभी माननीय सांसदों ने गॉवों का चयन कर इसकी सूची भी दे दिया।

दुख की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा नाममात्र से विकास नहीं होता इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, परन्तु भारत सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है तो आर्दश ग्राम कैसे बनेगा ?

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सांसदों से राज्य के 53 गॉवों की सूची भी प्राप्त हो गयी है। राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधन से जितनी योजनाएं चलायी जा रही थी, उन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि पुरा डी0पी0आर0 बनाकर तैयार रखे।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री चौधरी विरेन्द्र सिंह से मिलकर इस योजना के कार्यान्वयन मे हो रही दिक्कतों से अवगत कराया गया है। माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि जिन राज्यों में उद्योग की बेतहर हालत है, उन राज्यों को ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है। इस पर विचार करने को कहा है।

भारत सरकार या माननीय सांसद द्वारा उक्त गॉव के लिए राशि अलग से उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय, ताकि प्रधानमंत्री जी की सोच सफल हो सके।

क्र0 सं0	सांसद आदर्श ग्राम का नाम	प्रखंड	जिला	मा0 सांसद का नाम
	माननीय लोक सभा सांसद द्वारा अनुशंसित ग्राम			
1	निमौल	आजमनगर	कटिहार	श्री तारिक अनवर
2	नरमा नवीनगर	अलीनगर	दरभंगा	श्री कीर्ति झा आजाद
3	बरौरा	रामगढ़	कैमूर	श्री अश्विनी कुमार चौबे
4	नवानी	झंझारपुर	मधुबनी	श्री बिरेन्द्र कुमार चौधरी
5	घोड़ासाहन दक्षिण	घोड़ासाहन	पू0 चम्पारण	श्रीमती रामा देवी
6	तरतार	घोसवड़ी	पटना	श्रीमती वीणा देवी
7	बेलहवा मदनपुर		प0 चम्पारण	श्री सतीश चन्द्र दुबे
8	सिसवा सरैया	बैरिया	प0 चम्पारण	डॉ0 संजय जायसवाल
9	सितनावाद उत्तरी	सिमरी बख्यिारपुर	सहरसा	श्री चौधरी महबूब अली कैसर
10	नांनद	सिलाव	नालन्दा	श्री कौशलेन्द्र कुमार
11	धरौथ	मखदुमपुर	जहानाबाद	श्री अरूण कुमार
12	चादी	पूर्णिया पूर्व	पूर्णिया	श्री संतोष कुमार
13	इस्लामपुर पश्चिमी भीठा	इस्माइलपुर	भागलपुर	श्री शैलेश कुमार (बुलो मंडल)
14	वरियारपुर	डुमरा	सीतामढ़ी	श्री रामकुमार शर्मा कुशवाहा
15	अमियावार	नाशरीगंज	रोहतास	श्री उपेन्द्र कुशवाहा
16	बाकरपुर	बोधगया	गया	श्री हरि मांझी
17	जजवारा पश्चिम	कटरा	मुजफ्फरपुर	श्री अजय निषाद
18	एकरा	दिघलबैंक	किशनगंज	श्री मो0 असरारूल हक
19	मलहीपुर	चेनारी	रोहतास	श्री छेदी पासवान
20	दहियारी	सोनो	जमुई	श्री जिराग पासवान
21	अकबर मलाही	भगवानपुर	वैशाली	श्री रामविलास पासवान
22	कुबौली राम	पूसा	समस्तीपुर	श्री रामचन्द्र पासवान
23	बहुआरा	पातेपुर	वैशाली	श्री नित्यानंद राय

24	खारा आजम	बैकुंठपुर	गोपालगंज	श्री जनक राम
25	सरोजा बेला	मरौना	सुपौल	श्री रंजीता रंजन
26	सहुरिया	बनमा इटहरी	सहरसा	श्री राजेश रंजन (पप्पु यादव)
27	सितव दियारा	रिविलगंज	सारण	श्री राजीव प्रताप रूढ़ी
28	बारेजा	मांझी	सारण	श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल
29	जमुनिया	चकिया (पिपरा)	पू0 चम्पारण	श्री राधामोहन सिंह
30	सिमरिया–1	बरौनी	बेगूसराय	श्री भोला सिंह
31	खनवां	नरहट	नवादा	श्री गिरिराज सिंह
32	गुंडी पूर्वी	बड़हरा	भोजपुर	श्री राजकुमार सिंह
33	घोसौत	मीनापुर	मुजफ्फरपुर	श्री रामकिशोर सिंह
34	केसपा	टिकारी	गया	श्री सुशील कुमार सिंह
35	विधिपुर नरौली	बख्तियारपुर	पटना	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह
36	औराई पूर्वी	फारबिसगंज	अररिया	श्री तसलीमुद्दीन
37	जीरादेई	जीरादेई	सिवान	श्री ओमप्रकाश यादव
38	बनकटा	बेनीपट्टी	मधुबनी	श्री हुकुमदेव ना0 यादव
39	कोलहासर	कटोरिया	बांका	श्री जय प्रकाश नारायण यादव
40	सोनमई	दानापुर	पटना	श्री रामकृपाल यादव
	माननीय राज्य सभा सांसद द्वारा अनुशंसित ग्राम			
1	पिल्खी गायपट्टी	मुरौल	मुजफ्फरपुर	श्री अनिल कुमार सहनी
2	बकसरा	करगहर	रोहतास	श्री हरिवंश
3	पोकारी	मोदनगंज	जहानाबाद	श्री महेन्द्र प्रसाद
4	नोहसा	फुलवारी	पटना	श्री अली अनवर अंसारी
5	बैरिया	ब्रहमपुर	बक्सर	श्री वशिष्ठ नारायण सिंह
6	गोनपुरा	फुलवारी	पटना	श्री सी0पी0 ठाकुर
7	कोलौना	गुरूआ	गया	श्री गुलाम रसूल बलियावी
8	मानपुरा पश्चिम	पटना सदर	पटना	श्री आर0के0 सिन्हा
9	वाजिदपुर	जितवारपुर	समस्तीपुर	श्री रामनाथ ठाकुर
10	अलवारपुर	फतुहां	पटना	श्री रवि शंकर प्रसाद
11	बालम गधिया	मधेपुरा	मधेपुरा	श्री शरद यादव
12	साहजंगी	जगदीशपुर	भागलपुर	श्रीमती कहंकशा परवीन
13	लखानीबिगहा	दानापुर	पटना	श्री धर्मेन्द्र प्रधान